आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश शासन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

श्री अमित शाह

के

मुख्य आथित्य में

मध्यप्रदेश की वन समितियों का

सम्मेलन

मीडिया रिपोर्ट

22 अप्रैल 2022

जनसम्पर्क विभाग

मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

वन समितियों का सम्मेलन

एवं
वनग्राम को राजस्व ग्रा
बनाने का शुभारम्भ
ल, 2022, भोपाल

संबोधन

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

- पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है। इसका 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है।
- मध्यप्रदेश में 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। जब तक जनजाती भाइयों-बहनों का कल्याण नहीं होता, प्रदेश का कल्याण नहीं होता।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जो विचारधारा है गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को आप साकार करने का काम कर रहे हैं।
- आज एक ही बार में 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों को परिवर्तन किया है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का फैसला है। राज्य में हमारा भी हिस्सा है इस अधिकार के साथ आज यहां से जा रहे हैं।
- 2022 के अंत के पहले अपना घर देने का संकल्प श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हर घर में बिजली पहुंचाने, शौचालय बनाने का काम समाप्त हो गया है।
- हर घर में जल, नल से पहुंचाने का प्रयोग शुरू हो गया है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा ।
- दस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 2 सौ प्रतिशत की वृद्धि मध्यप्रदेश ने की है। ये रुकने वाले कार्य नहीं है। जितने भी कार्य जनजाति भाइयों के लिए हमने घोषित किए हैं वे सभी पूरे होंगे।

संबोधन

श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे वे एक-एक करके जमीन पर उतार रहे हैं और गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। 89 जनजतीय ब्लॉक में राशन की गाड़ी भेजने कहा था, मुझे कहते हुए खुशी है वह राशन बंटना अधिकांश स्थानों पर प्रारंभ हो गया है।
- पेसा एक्ट क्रमश: मप्र में लागू किया जाएगा, मप्र में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी, उसकी आय आप ही प्राप्त करो।
- जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी, मप्र ने अपने वनवासी भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा।
- अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा।
- तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा, लाभांश आपको होगा।

वनवासियों को जंगल की मालिकी दिलवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश, वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने वाला देश का पहला राज्य है। मध्यप्रदेश ने यह युग परिवर्तनकारी कार्य किया है। गत सितंबर माह में जबलपुर में जनजातीय समाज के विकास के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूर्ण करने में मध्यप्रदेश सरकार सक्रिय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन घोषणाओं को पूरा करते हुए अमल में लाना प्रारंभ कर दिया है। अंग्रेजों के समय से सरकार के पास जंगलों का स्वामित्व था। अब मध्यप्रदेश में कीमती सागवान लकड़ी के साथ ही अन्य वन संपदा की 20% राशि के मालिक वनवासी होंगे। जनजातीय समुदाय के हक में लागू की गई ये बड़ी पहल है। मध्यप्रदेश में देश की सबसे अधिक 21% जनजाति आबादी निवास करती है। इनके कल्याण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह आज जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश को

बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निरंतर कार्य किया है। मध्यप्रदेश अब विकसित राज्यों में शामिल है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, पर्याप्त बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य शिवराज जी के नेतृत्व में हुए हैं। जनजातीय क्षेत्र कल्याण के लिए मध्यप्रदेश की पहल पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि वनवासी क्षेत्र के सभी लोग अधिकार के साथ जिये, यह उनका स्वप्न है, जिसे साकार किया जा रहा है। आज बाँस और अन्य उत्पादन के लिए राशि वितरण के साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों को करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। मध्यप्रदेश के 925 में से 827 वन ग्राम को राजस्व ग्रामों की तरह सुविधाएँ देने की शुरुआत हुई है। यहाँ परिसिमन हो सकेगा, आवास के लिए ऋण मिल सकेगा और राजस्व के सभी अधिकार वनवासियों को प्राप्त होंगे। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि वनवासी आज स्वाभिमान के भाव के साथ वापस जाएंगे। प्रदेश में 15 हजार 600 से अधिक ग्राम सभाओं में वन समितियों के माध्यम से प्राथमिकता से कार्य किए जा सकेंगे।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि सरकार को प्रधानमंत्री श्री मोदी समाज के वंचित और दलित वर्गों की सरकार की पहचान देने में सफल रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक सभी को अपना घर देने का भी संकल्प है। श्री शाह ने कहा कि देश में शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला के 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए है। हर घर में नल से जल पहुँचाने की पहल जल जीवन मिशन से हो रही है। वर्ष 2024 तक यह कार्य पूरा होगा। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है। कोरोना काल में नि:शुल्क अनाज देने की सुविधा दी गई। वैक्सीनेशन का लाभ नागरिकों को दिया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना में

खाद्यान्न वितरण के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार की महिलाओं को 1000 रूपये का आहार अनुदान भी दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश द्वारा 19.7 प्रतिशत विकास दर हासिल करना बड़ी बात है। मध्यप्रदेश में गत 10 वर्ष में 200% सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, जो अन्य राज्यों में नहीं हुई। प्रदेश में पूँजीगत व्यय 31 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 40 हजार करोड़ तक हो गया है। भारत सरकार ने भी मध्यप्रदेश को 11 हजार करोड़ रूपये प्रदान किये हैं। जनजातीय वर्ग के कल्याण का बजट 4 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 7 हजार 524 करोड़ रूपये हो गया है। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास के लिये पूर्व सरकार की 21 हजार करोड़ की राशि को बढ़ाकर 78 हजार करोड़ रूपये तक पहुँचा दिया है। एकलव्य विद्यालयों के लिये 14 हजार 18 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिये विशेष कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी टीम को बढ़ते मध्यप्रदेश और जनजातीय वर्ग के कल्याण के ऐतिहासिक कार्य के लिए साधुवाद एवं बधाई दी।

827 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने रिमोट से बटन दबाकर वन ग्राम की जस्व ग्राम बनाने के कार्य की शुरुआत की। इस कार्य के लिए प्रदेश के 26 जिलों के 827 ग्राम चयनित किए गए हैं।

वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से वनवासियों की सँवर जाएगी जिंदगी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के साथ ही

आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए कार्य किया है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सभी दिशाओं में कार्य हो रहा है। प्रदेश में हरियाली को वनवासियों के सहयोग से बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन वितरण का कार्य हुआ है। जनजातीय बहुल विकासखंडों में घरों तक राशन पहुँचाने का कार्य किया गया है। वनवासियों के ही हित में पेसा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया गया है।इससे वनवासियों का हित होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह जल, जमीन और जंगल वनवासियों के हैं। वनों से अर्जित आय का हिस्सा प्राप्त कर वनवासी, वनों के विकास में सहयोग करेंगे। वन विभाग सहयोगी की भूमिका में होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है, इसका लाभ जनजाति वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग के लोगों को शिक्षण शुल्क सुविधा, उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और रोजगार के साधनों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया पर नियंत्रण के लिए भी कार्य हो रहा है। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल भी इस कार्य में मार्गदर्शन दे रहे हैं। वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बन जाने से बँटवारा और नामांतरण होने के साथ फसलों की गिरदावरी भी हो सकेगी। प्राकृतिक आपदा पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, आँगनवाड़ी और विद्यालय भवन स्वीकृत होंगे और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। तालाबों का निर्माण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज प्रदेश के 22 लाख हितग्राहियों के खाते में 125 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। यह वनवासी भाई-बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 250 रुपये प्रति सौ गड्डी के स्थान पर अब 300 रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफियाओं से 21 हजार एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। इस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख आवास निर्मित हुए हैं। इस वर्ष 10 लाख और अगले वर्ष भी 10 लाख आवास निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए 10 हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। आयुष्मान योजना का लाभ नागरिकों को मिल रहा है। संबल योजना पुन: प्रारंभ की गई है। कोरोना काल में विद्युत देयक संबंधी राहत देकर शासन ने 6400 करोड़ रुपये के देयकों को स्थगित किया है।

कन्या विवाह योजना में अब 55 हजार रुपये की राशि दी जा रही है

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय जनशक्ति और खाद्य प्र-संस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मत्स्य-पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल. मुरुगन, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्री कल सिंह भाबर, मध्यप्रदेश के वन मंत्री श्री विजय शाह, गृह, जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह उपस्थित थे।

सम्मेलन के प्रारंभ में बुंदेलखंड के प्रख्यात लोक नृत्य "बधाई" की प्रभावशाली प्रस्तुति हुई। केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह को जनजातीय संस्कृति के प्रतीक पारंपरिक तीर-कमान और जैकेट भी भेंट किए गए। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री-मंडल के सभी सदस्यों के साथ भेंट की। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

हितग्राहियों को दिये गये हित-लाभ

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 5 तेंदूपत्ता संग्राहकों श्रीमती ललिता बाई सीहोर, श्रीमती संतोष रायसेन, श्री अमर सिंह नर्मदापुरम, श्री सजन सिंह देवास और श्रीमती लक्ष्मीबाई हरदा को प्रतीक स्वरुप प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्रदान किया। छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा जिले की वन समिति की वन समितियों को लाभांश प्रदान किया गया।

वन मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में वनों को बचाते हुए समग्र विकास की दिशा में कार्य हो रहा है। जंगल न कटे, वनवासी इसे अपना समझें, उन्हें 20% लाभांश देने वाली यह पहली सरकार है। प्रदेश में करीब एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार को वनों से आय मिलती थी। अब उसका हिस्सा वनवासियों को मिलेगा।

प्रदर्शनी का अवलोकन

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कार्यक्रम स्थल पर वन विभाग द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में वनों के विकास, वन समितियों के कार्यों और वन उत्पाद के संबंध में अर्जित उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। नरसिंहपुर जिले के सतपुड़ा रस्सी निर्माण केंद्र द्वारा रस्सी निर्माण के कार्य का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने समिति के सदस्यों से रस्सी निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न उत्पादों का अवलोकन कर प्रदर्शनी की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में वन विकास के कार्यों की जानकारी दी।

■■

सफलता की कहानी

मध्यप्रदेश की वन समितियों ने किया शानदार काम

लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार

मध्यप्रदेश में सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन, संरक्षण एवं सुधार की दिशा में वन समितियों के माध्यम से शानदार काम किया गया है जो पूरे देश में अनूठा है। इन वन समितियों से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से भी सशक्त हुए हैं।

प्रदेश का वनक्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर है जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह देश के कुल वन क्षेत्र का 12.3% है। प्रदेश के 79 लाख 70 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रबंधन में जन-भागीदारी के लिये 15 हजार 608 गाँवों में वन समितियाँ काम कर रही हैं। पिछले एक दशक में 1552 गाँवों में वन समितियों ने 4 लाख 31 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुधार किया है। जब पूरी दुनिया में वनों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय इन समितियों ने वन विभाग के साथ मिलकर शानदार काम किया है।

राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, वनोपज संग्रह करने वाले परिवारों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। संघ के नवाचारी उपायों से तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। तेंदूपत्ता सीजन में 2021 कोविड-19 के कारण लॉक-डाउन के बाद भी तेंदूपत्ता संग्रहण कराकर दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय परिवारों को 415 करोड़ रूपये का पारिश्रमिक दिलाया गया और 192 करोड़ का लाभांश भी वितरित किया गया।

पुरानी नीति में 70 फीसदी लाभांश संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाता था। साथ ही 15% राशि

वन समितियों के उल्लेखनीय काम

सतना की ग्राम वन समिति गोदीन ने गोंड जनजाति की महिलाओं को सॉफ्ट टॉय बनाने का प्रशिक्षण ग्रीन इंडिया मिशन में दिया है। इसी प्रकार सीधी वन मंडल की ग्राम वन समिति बम्हनमरा ने बिगड़े वन क्षेत्र में काम करना शुरू किया और अवैध कटाई, चराई, अतिक्रमण से जंगलों की सुरक्षा की। समिति को महुआ फूल, गुल्ली, अचार, जलाऊ लकड़ी मिल रही है।

बालाघाट की ग्राम समिति अचानकपुर ने बाँस-रोपण क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। बाँस के दोहन से समिति को एक लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। वन मंडल सीधी की ग्राम वन समिति ने वन विहीन पहाड़ी में काम करना शुरू किया और अपने परिश्रम से इसे सघन सागौन वन में बदल दिया। समिति को सागौन की बल्लियों से आर्थिक लाभ भी हुआ। वन मंडल पश्चिम मंडला की ग्राम वन समिति मनेरी ने वन विहीन पहाड़ी को हरा-भरा बना दिया। इसी प्रकार अन्य समितियाँ भी अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार के सहयोग से शानदार काम कर रही हैं।

संग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए और 15% राशि वन क्षेत्रों में लघु वन उपज देने वाली प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास पर खर्च की जाती थी। अब "पेसा अधिनियम" की भावना के अनुसार तेंदूपत्ता के व्यापार से होने वाले लाभ का 75% संग्राहकों को, 10% राशि संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए और 10% राशि वन क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के संरक्षण तथा 5 प्रतिशत ग्राम सभाओं को दी जाएगी।

वन विभाग द्वारा नए संकल्प में राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के प्रवेश से मिलने वाली राशि का 33% वन समितियों को देने का प्रावधान किया गया है । समितियों को आवंटित क्षेत्र में ईको पर्यटन का कार्य संचालित करने के लिए सशक्त किया गया है। इससे

होने वाली आय वन समिति को मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को आर्थिक गतिविधियाँ शुरु करने के अवसर मिलेंगे।

वन समितियों का माइक्रो प्लान

प्रदेश के एक तिहाई गाँव वन क्षेत्रों के अंदर या उसके आसपास बसे हैं। वहाँ के निवासियों की आजीविका वनों पर आधारित है।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में इस साल के आखिर तक 5 हजार वन समितियों का माइक्रो प्लान तैयार करने का लक्ष्य है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ग्राम समुदाय अपनी आवश्यकता की वनोपज का उत्पादन कर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

लाभांश में वृद्धि

वन समितियों को दिए जाने वाले लाभांश में वृद्धि की गई है। पहले जिला स्तर पर शुद्ध लाभ की राशि का 20 फीसदी मिलता था, जिसकी वजह से राशि का वितरण केवल कुछ ही जिलों में हो पाता था। अधिकांश समितियाँ लाभ से वंचित रह जाती थी। नए संकल्प के अनुसार प्रत्येक समिति को उसके क्षेत्र में से किए गए दोहन से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पहले काष्ठ एवं बाँस का 50 करोड़ रुपए तक का लाभांश वितरण होता था। अब लगभग 160 करोड़ प्रति वर्ष हो रहा है।

ग्राम सभाओं को सौंपा अधिकार

वन समितियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का अधिकार अब ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। वन समिति की कार्यकारिणी में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लोगों को शामिल करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में अनेक प्रकार की वनोपज का उत्पादन होता है। इसमें महुआ, तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और चिरौंजी प्रमुख है। पेसा कानून की भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों का पूरा अधिकार सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ऐसे निर्णय लिये गये हैं, जो वन समितियों से जुड़े संग्राहक परिवारों के लिये परिवर्तनकारी साबित हुए हैं। वन समितियों को भरपूर आर्थिक लाभ हुआ है। उदाहरण के लिये 32 वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से करीब 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। तेंदूपत्ता व्यापार के शुद्ध लाभ का 70 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत देने से 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है।

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में लगातार वृद्धि की गई है। इसी के अनुपात में पारिश्रमिक और बोनस का भुगतान भी किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2005 में प्रति मानक बोरा ₹400 थी, जो अब बढ़कर 2500 सौ रूपये प्रति मानक बोरा हो गई है। पारिश्रमिक का भुगतान वर्ष 2005 में ₹67 करोड़ रूपये होता था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 415 करोड़ रूपये हो गया है। संग्राहकों के बच्चों के लिए एकलव्य शिक्षा योजना पिछले ग्यारह साल से चल रही है, जिससे अब तक 1712 बच्चों को शिक्षा के लिये 2 करोड़ एक लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

■■

कटनी जिले के मझगवां बीट की वीरान पहाड़ी में जी उठा जंगल

समाज की लापरवाही और मनुष्य द्वारा लगातार जंगल काटे जाने की वजह से कुछ साल पहले तक कटनी जिले के मझगवां की पहाड़ी गिने-चुने पेड़ों के तनों के ठूंठ और जंगली झाड़ियों तक सिमट गई थी, आज वहां मिश्रित प्रजाति के हजारों पेड़-पौधे लहलहा रहे हैं। अब यह पहाड़ी ग्रामीणों की जनसहभागिता और संयुक्त वन प्रबंधन से बिगड़े वनों के सुधार की मिसाल बन चुकी है।

करीब 652 हेक्टेयर क्षेत्र के इस मरते हुए वन को वन समिति की सहभागिता और सक्रियता से नया जीवन मिला। पेड़-पौधों से उजाड़ और वीरान हो चुकी मझगवां की इस पहाड़ी में अब जंगल जी उठा है। दरअसल कटनी शहर के नजदीक होने के कारण अत्यधिक जैविक दबाव, जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति एवं आस-पास के ग्रामीण इलाकों के करीब 4 हजार से अधिक पालतू पशुओं की चराई भी इसी वन क्षेत्र पर निर्भर थी। जिससे मझगवां का पूरा जंगल बिगड़े वन क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था।

मझगवां बीट के आरएफ-107,108 से मझगवां, बंजारी, पौड़ी, छैगरा, बिजौरी, उमड़ार गांव से लगा वन विभाग का 652 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट है। मझगवां वन समिति के अध्यक्ष संतराम कुशवाहा ने बताया कि कुछ साल पहले जंगल नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गया था। वन विभाग ने इस क्षेत्र में वन सुधार के तहत काम करना शुरु किया और उसमें वन समिति के सदस्यों की मदद ली गई। 11 सदस्यीय वन ग्राम समिति ने वन विभाग के साथ पौधे रोपने के साथ ही उनके वृक्ष बनने तक और पुराने पेड़ों को सुरक्षित रखने की कवायद शुरु की। उसका नतीजा यह है कि 652 हेक्टेयर वन भूमि आज हरी-भरी हो चुकी है।

शहर से लगा यह वन क्षेत्र जहां आमजनों को आकर्षित करता है, तो वहीं जंगल में वन्य प्राणियों को भी रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिल रहा है। यहां पर वन विभाग ने वन्य प्राणियों के पानी पीने के लिए समाजसेवी संस्था के माध्यम से पौंसरा की व्यवस्था की है। आज जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर, चीतल,

वन समितियों के साथ

चौकीदार भी करते हैं सुरक्षा

652 हेक्टेयर के रिजर्व फारेस्ट के पेड़ों व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वर्तमान वन समिति अध्यक्ष संतराम कुशवाहा के साथ ही उपाध्यक्ष कत्ती बाई, सदस्य चुटुवादी कोल, प्रीति कुशवाहा, बोधन प्रसाद चौधरी, लक्ष्मण प्रसाद सोनी, सुभाष कुशवाहा, संतोष कोल, सिकंदर कोल, बापी तरफदार भी रिजर्व फारेस्ट के पेड़ों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। बीट गार्ड शक्तिपाल सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वन क्षेत्र को सुधारने और पेड़ों, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए दो चौकीदार फूलचंद कोल व दुलीचंद कोल को भी तैनाम किया गया है, जो वर्षों से ग्रामीणों, वन समितियों के सदस्यों के सहयोग से वन व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में 24 घंटे सेवाएं देते हैं।

पहाड़ी के आसपास के ग्रामीणों को अब इस जंगल से गिरी-पड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी के अलावा तेंदूपत्ता, महुआ, अचार एवं अन्य वन औषधीय वनोपज उत्पाद भी प्राप्त हो रहे हैं। समिति द्वारा इन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या इससे अधिक दर पर विक्रय कर लाभांश के रूप में आय अर्जित हो रही है।

सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय सहित अन्य वन्य प्राणी निर्भय होकर विचरण करते हैं, जो यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं।

वन मंडलाधिकारी कटनी आरसी विश्वकर्मा बताते हैं कि इस पहाड़ी को हरा-भरा करने में ग्रामीणों की समझ और सहभागिता देखने को मिली, वो प्रशंसनीय है। वन समिति के सदस्यों ने न केवल पेड़ों की देखरेख की बल्कि कटाई करने वालों को जंगल और पेड़ों का महत्व बताकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि सही मायनों में ग्रामीण ही इस पहाड़ी के पेड़-पौधों के सबसे बड़े रखवाले हैं। इनकी जिद और जुनून ने ही पहाड़ी को हरा-भरा कर दिया है।

रेंजर एल.एन. चौधरी ने बताया कि अब इस पहाड़ी के घने जंगल में चीतल, सांभर, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर और सियार बड़ी संख्या में हैं साथ ही अनेक प्रजातियों के पक्षियों का भी कलरव सुनाई देता है।

■ ■

बहुआयामी मंधान जलग्रहण क्षेत्र उपचार परियोजना से वन क्षेत्रों में वन भूमि व जल संरक्षण के साथ ही हितग्राही हो रहे हैं लाभान्वित

प्रदेश सरकार द्वारा वन प्रबंधन और बिगड़े वन क्षेत्रों को व्यवस्थित करने की दिशा में बेहतर कार्य किये जा रहे हैं तथा छिंदवाड़ा जिले में भी जहां वन क्षेत्रों में वन, भूमि व जल संरक्षण के बेहतर कार्य किये जा रहे हैं, वहीं हितग्राहीमूलक आजीविका कार्य भी किये जा रहे है जिससे हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री के.के.भारव्दाज व कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन एवं पश्चिम वनमंडल के वनमंडलाधिकारी श्री ईश्वर जरांडे के निर्देशन में पश्चिम वनमंडल द्वारा क्रियान्वित की जा रही जिले के विकासखंड परासिया की मंधान नदी पर केन्द्रित मंधान जलग्रहण क्षेत्र उपचार परियोजना एक ऐसी बहुआयामी परियोजना है जिसके सकारात्मक परिणामों से बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार होने के साथ ही भूमि व जल संरक्षण भी हुआ है और परियोजना क्षेत्र के हितग्राहियों की आजीविका आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई है। इस परियोजना में पश्चिम वनमंडल के परासिया, जुन्नारदेव और तामिया वन परिक्षेत्रों के 24 ग्राम शामिल हैं। इस परियोजना से जलग्रहण क्षेत्र में शामिल ग्रामों में प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण बना हुआ है।

पश्चिम वनमंडल के वनमंडलाधिकारी श्री जरांडे ने बताया कि जिले के विकासखंड परासिया की मंधान नदी पर 10 करोड़ 74 लाख एक हजार रूपये लागत की मंधान जलग्रहण क्षेत्र उपचार परियोजना संचालित की जा रही है। पेंचव्हेली क्षेत्र की मंधान नदी जो पेंच नदी की उपनदी है, पर बनाये गये मंधान बांध जिसकी जल रोकने की क्षमता 53 एम.सी.एम. है, में इस

परियोजना के मास्टर प्लान में जलग्रहण क्षेत्र का कैम्पा के माध्यम से समग्र उपचार का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ यह परियोजना वर्ष 2028-29 तक क्रियान्वित की जायेगी। इस परियोजना का कुल भौगोलिक क्षेत्र 16 हजार 27 हेक्टेयर है, जबकि कुल 10 हजार 878 हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपचार किया जा रहा है। परियोजना में पश्चिम वनमंडल के परासिया, जुन्नारदेव और तामिया परिक्षेत्रों के 24 ग्रामों के 3 वॉटरशेड और 15 माईक्रो वॉटरशेड शामिल है। परियोजना के अंतर्गत जहां वन क्षेत्र के साथ ही भूमि व जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, वहीं हितग्राहीमूलक आजीविका कार्य भी किये जा रहे है। परियोजना के अंतर्गत 6 करोड़ 48 लाख 68 हजार रूपये लागत से अभियांत्रिकी कार्य, 2 करोड़ 45 लाख 45 हजार रूपये की लागत से जैविक कार्य, 75 लाख रूपये की लागत से आस्थामूलक कार्य, 73 लाख रूपये की लागत से नर्सरी कार्य और 31 लाख 88 हजार रूपये की लागत से अन्य कार्य कराये जा रहे है। परियोजना प्रारंभ से लेकर माह फरवरी 2022 तक इस परियोजना के अंतर्गत 3 करोड़ 56 लाख 66 हजार रूपये के कार्य हो चुके हैं जिसमें एक करोड़ 68 लाख 36 हजार रूपये लागत के अभियांत्रिकी कार्य, एक करोड़ 39 लाख 80 हजार रूपये की लागत के जैविक कार्य, 20 लाख 50 हजार रूपये की लागत के आस्थामूलक कार्य और 28 लाख रूपये की लागत के नर्सरी और अन्य कार्य शामिल है।

मंधान नदी का जलग्रहण क्षेत्र तीव्र पहाड़ी उथली मृद्रा वाला क्षेत्र है, जो भू-क्षरण के लिये अत्यंत प्रबल है। वन क्षेत्र का प्रतिशत कम है और जो वन क्षेत्र मौजूद है, वह विरल व जैविक दबाव के कारण बिगड़ा वनक्षेत्र है। इस प्रकार से जलग्रहण क्षेत्र में मृदा अवसादन के कारण बांध की उपयुक्त आयु कम हो जाती है और जलग्रहण कम होने के कारण पानी सतह से बहकर पानी की वार्षिक उपलब्धता भी प्रभावित होती है। जलग्रहण उपचार परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र में मृदा क्षरण को रोकना और पानी का भूमि में रिसाव बढ़ाना है। इस परियोजना में कुल 29.97 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें से 17.725 हेक्टेयर वनभूमि है। मंधान नदी का जलग्रहण क्षेत्र 24 गांव में विस्तारित है, जिसमें से 6 गांव पूर्णतः और 18 गांव अंशतः जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं। समस्त गांवों में कृषि

मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय है। प्रति किसान भूमि कम है और मिट्टी उथली व मुरमी किस्म की है। परियोजना में आस्थामूलक कार्य भी शामिल किये गये है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों का परियोजना में सहभागिता बढ़ाना और परियोजना को सफल बनाने में मदद करना है। परियोजना के अंतर्गत कम ढलान वाले क्षेत्र जहां पानी का बहाव तीव्र नहीं है, वहां 19425 घनमीटर के 1549 लूज बोल्डर चेकडेम बनाये गये है जिससे 250 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र जहां पानी का बहाव तीव्र है, ऐसे स्थानों पर 5299.247 घनमीटर की 92 गेबियान संरचना तैयार की गई है जिससे 150 हितग्राही लाभान्वित हुये है। इसी प्रकार 1218.50 घनमीटर के कंटूर ट्रेंच बनाये गये है जिससे 40 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं। कृषकों के खेतों में मृदा व जल संरक्षण के लिये 922 रनिंग मीटर कंटूर बंड बनाये गये है जिससे कृषकों की मेढ़ों से मृदा का क्षरण कम होने के साथ ही उपलब्ध बंजर जमीन में खेती करना संभव हो रहा है। क्षेत्र के 83 कुओं में जल स्तर बढ़ा है तथा 10 हितग्राहियों के कुओं में कुआं दांसा का निर्माण कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

परियोजना क्षेत्र के 5 स्थानों पर 47 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया है जिससे 130 हितग्राही लाभान्वित हुये है। हितग्राहियों को पौधे उपलब्ध कराने के लिये नर्सरी की स्थापना की गई है तथा इस नर्सरी में 2 लाख 35 हजार पौधे तैयार कर 650 किसानों को एक लाख 18 हजार 398 पौधे उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है। इस वर्ष भी किसानों के मेढ़ों पर लगाने के लिये लगभग 3 लाख फलदार पौधे तैयार किये जा रहे हैं। किसानों को प्रेरित करने पर 149 किसानों द्वारा 22 हजार किलोग्राम जैविक खाद तैयार की गई है तथा इस खाद का उपयोग मक्का, धान आदि फसलों में किया है जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। 16 किसानों की गौ-शालाओं में फर्श का निर्माण कराया गया है जिससे गौ-मूत्र एकत्रित कर टॉनिक व कीटनाशक तैयार किया जा रहा है। साथ ही इस वर्ष किसानों को गिर/साहिवाल गाय उपलब्ध कराई जायेंगी। केचुआ खाद के लिये 50 किसानों को ट्रेटापैक वितरित कर लाभान्वित किया गया है। मुर्गीपालन के लिये 4 हितग्राहियों को अंडे देने वाली मुर्गियां उपलब्ध कराई गई हैं तथा इस वर्ष भी लगभग 100 परिवारों में प्रत्येक परिवार को 10 अंडे देने वाली मुर्गियां उपलब्ध कराई जायेंगी। अभी तक लगभग 30 प्रतिशत व्यय पर ही यह उपलब्धि हासिल की गई है तथा आगामी समय में तीव्र गति से और अधिक उपलब्धि हासिल हो सकेगी। जलग्रहण क्षेत्र में उपचार और अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन में मात्र बहुत ही कम समय में आम जनता की इस परियोजना में सक्रिय सहभागिता बढ़ी है और वे उत्साहपूर्वक सहयोग कर रहे हैं जिससे बेहतर व अच्छे परिणाम दिखाई देना शुरू हो गये हैं और आगे भी दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिल सकेंगे।

■ ■

कुलुवा में पहले जंगल की स्थिति बंजर थी धीरे-धीरे हरे होते गए जंगल जो आज फल-फूल रहे हैं

ग्राम वन समिति के पूर्व अध्यक्ष रुपलाल मिश्रा कहते है, "पहले मैं ग्राम पंचायत कुलुवा का सरपंच था, उस समय सरपंच पद ग्रहण करने के बाद सभा हुई, उस सभा में कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि आप सरपंच बन गए हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं क्षेत्र की भूमि का भौगोलिक नक्शा तैयार करूंगा। इस भौगोलिक वन क्षेत्र में कितने गांव आते हैं, इस क्षेत्र पर कितने गांव का दबाव है का आंकलन करने सबसे पहले मैंने इस भौगोलिक क्षेत्र का वन विभाग के नक्शे से कक्ष क्रमांक 417, 418, 419, 420, 421, 422 एवं 423 में इसका सर्वे करवाया, तो यह रिजल्ट आया कि यहां 3668 हेक्टेयर वन भूमि थी।"

वे कहते हैं, "उस समय मुझे लोगों की अच्छी उत्सुकता दिखी कि हम जंगल बचाएं। मैंने सभी से प्रश्न किया कि सभी लोग सहयोग करेंगे तो पंचायत के माध्यम से समिति बनायेंगे। आप सभी वनो की सुरक्षा करना और जंगल बना लेना, यह जंगल सभी के काम में आएगा। बहुत सी चीजें जंगल में उपयोगी होंगी, जिससे आपकी आय बढ़ जाएगी और 3668 हेक्टेयर भूमि पर 12 समितियां गठित की गई। इसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उस समय वन मंत्री जी, वन विभाग से सीसीएफ और अधिकारी आए, तब समिति के लोगों से शपथ कराई कि ना हम पर पेड़ काटेंगे और ना ही किसी को पेड़ काटने देंगे। हर समिति में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई पेड़ काटता है तो उसका 100 जुर्माना करके समिति में जमा करेंगे। यदि साइकिल पर पेड़ काट कर ले जाता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा और साइकिल जब्त करके साइकिल की नीलामी समिति करेगी, उसकी जो आय होगी वह समिति में जाएगी।"

तब से लोगों में एक बहुत बड़ी जागरूकता आई, सबसे पहले यहां पर 200 से 300 एकड़ भूमि में अतिक्रमण था आसपास के गांवों में अतिक्रमण को हटाया यह पूरा क्षेत्र वनविहीन था। संकल्प लिया गया कि इस भूमि को सघन वन बनाना है। सभी सहयोगी ग्रामीणों ने महिलाओं से लेकर पुरुषों और बच्चों ने संकल्प लिया कि वृक्षों को नहीं काटेंगे। धीरे-धीरे यह सघन वन बन गया। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत समिति कुलुवा को पुरस्कृत किया गया।

उन्होंने बताया 40 हेक्टेयर भूमि में इसको मिश्रित वन घोषित करवा कर इसमे वृक्षारोपण का कार्य करवाया, जब इसका रिजल्ट अच्छा आया तो 2015 में फिर से प्लांटेशन करवाया। फिर सोचा जितना ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे तो गांव के लोगों को गड्ढा खोदने में, पौधा लगाने में, चौकीदारी करने एवं वन के चारों तरफ तार फेंसिंग करने में रोजगार मिलेगा, जंगल की सफाई होगी उसमें भी रोजगार मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर यहां पर 6 प्लांटेशन तैयार करवाए।

उन्होंने कहा कुलुवा में पहले जंगल की स्थिति बंजर थी धीरे-धीरे जंगल हरियाली में परिवर्तित हुआ फिर स्थिति बहुत अच्छी हुई, उस समय जंगल में सम्मेलन किया गया यहां पर 8 हजार लोग एकत्रित हुए थे जिसमें से 5 हजार लोगों ने संकल्प लिया कि ना हम जंगल काटेंगे और ना ही किसी को काटने देंगे साथ ही अपने खेतों में भी पेड़ लगाएंगे। सर्वप्रथम यहां 40 हेक्टेयर में मिश्रित प्लांटेशन लगाया गया।

कुलुवा निवासी श्री राजपूत ने कहा, "कुलुवा समिति की यह सारी जमीन हैं। इस जंगल में जानवर भी रहते हैं, पहले यहा पर कुछ नहीं था। पंडित जी ने मेहनत की और सभी लोगो का सहयोग रहा जिससे यह जंगल बचा इसमे जो जानवर हैं और जो भी लाभदायक पेड़ आवला और भी अन्य पेड़ लगवाए गये हैं जिससे हम लोगों को भी फायदा हैं। जंगर से गायो के लिए घास मिल रही हैं।"

कुलुवा में पदस्त बीट गार्ड पवन सिंह ठाकुर ने कहा, "यहां पर 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन हैं। यहा पर पेड़ों की कई प्रजातियां लगाई गई हैं और मिश्रित वृक्षारोपण हैं। वृक्षों में यहाँ पर आंवला, शीशम, नीम, सागौन, करंज, खामेर, महुआ, कोहा, जामुन एवं अन्य प्रकार के पेड़ लगाए गये हैं। यहां पर हरियाली के कारण जानवर भी आ गये हैं। जानवरो में यहां जंगली सूअर, छिकरा, हिरण खरगोस एवं नीलगाए है।

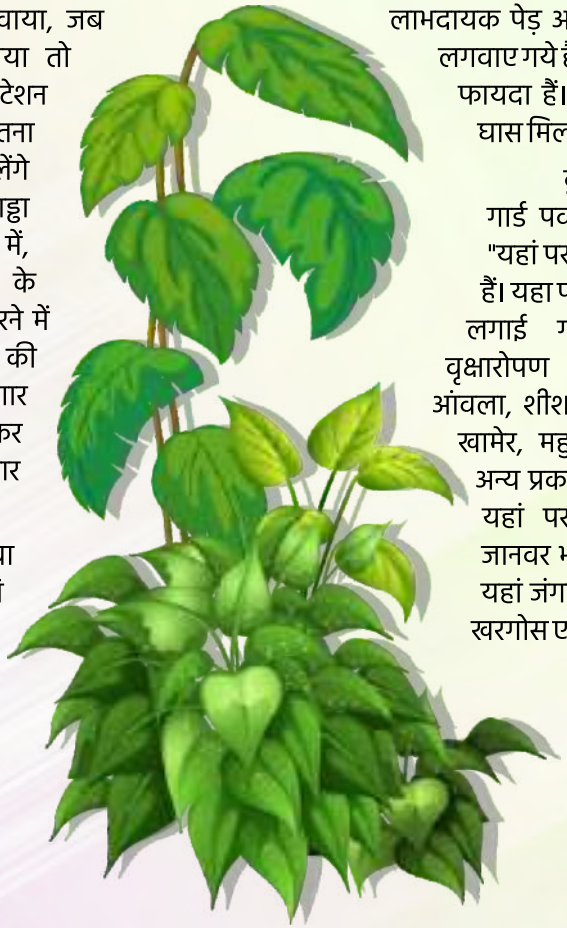

सफलता की कहानी

जिला - दमोह

दो गांवों के निवासी मिलकर कर रहे वन की सुरक्षा

सगौनी परिक्षेत्र के अंतर्गत बीट बनवार में ग्राम वन समिति झरौली को सुरक्षा की दृष्टि से कक्ष क्रमांक आर.एफ. 412 में समिति को 207.76 हेक्टेयर रकवा आवंटित है। ग्रामीण बताते हैं कि श्री श्री 1008 परम पूज्य गुरु श्री विष्णुदत्त तिवारी जी ने सन् 1992 में दोनों ग्राम मुँवार और झरौली के बीच में सिद्ध बाबा क्षेत्र में इनके शिष्यों को यज्ञ कराने की सलाह दी थी। यज्ञ समाप्ति के पश्चात ग्राम मुँवार और झरौली के ग्राम वासियों से वृक्षों के संरक्षण का संकल्प कराया गया। साथ ही ये तय किया गया कि अगर मुँवार ग्राम का व्यक्ति वृक्ष काटता है, तो झरौली के लोग जो भी जुर्माना बताएंगे, वो उस व्यक्ति को मंजूर करना पड़ेगा। इसी तरह झरौली ग्राम के व्यक्तियों के द्वारा वृक्षों की कटाई की जाती है, तो वही शर्त एवं नियम उनपर लागू होंगे।

सर्व प्रथम ग्राम वन समिति झरौली का गठन पश्चात अध्यक्ष के पद पर प्रकाशचंद जैन रहे। दूसरी बार अध्यक्ष झरौली का गठन किया गया जिसमें देवीसींग ठाकुर को अध्यक्ष बनाया गया एवं उपाध्यक्ष पद हेतु प्रीति जैन व सहसचिव देवी सींग ठाकुर को बनाया गया। तीसरी बार ग्राम वन समिति गठन के पश्चात अध्यक्ष पद हेतु खिलान सींग ठाकुर को मनोनीत किया गया। इस प्रकार सभी ग्राम वासियों एवं समिति अध्यक्षों का वृक्षों के संरक्षण के प्रति लगाव व सहयोग भरपूर सहयोग रहा। उस समय वृक्षों की कटाई होने पर अर्थ दंड के रूप में जो भी राशि ली गई उस राशि का उपयोग सिद्धबाबा क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु दोनो ग्राम वासियों की सहमति से किया गया।

वर्तमान मे भी दोनों ग्राम वासियों के सहयोग से वह परम्परा आज भी चल रही है एवं सिद्ध बाबा क्षेत्र में वृक्षों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सिद्ध क्षेत्र में लगे वृक्षों की हरियाली एवं सौदर्य सुहावना व रमणीय है। वहां जो भी लोग सिद्ध बाबा क्षेत्र में दर्शन हेतु आते है

- ग्राम वन सिमति झरौली के वृक्षों का सरंक्षण
- ग्राम मुवार में आज भी वर्षो पुराने लगे पेड़ सुरक्षित

वहां का दृश्य देखकर वृक्षों के संरक्षण के प्रति ग्राम वासियों के द्वारा किए गये वृक्षों के संरक्षण कार्य की सराहना करना भी नहीं भूलते हैं एवं उन सभी से प्रेरणा भी पातें है। ग्रामीणों के अनुसार यह परम्परा स्वर्गीय श्री श्री 1008 परमपूज्य गुरु देव जी की कृपा का फल है। गुरूदेव के वचनों का पालन करके समिति सदस्यों ने वन सुरक्षा में वन विभाग का सहयोग किया है जो कि प्रशंसनीय है।

झरौली मुँवार ग्राम से अजमेर सिंह ने बताया यह पूरा क्षेत्र लगभग 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहां पर सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहीं पर दोनों गांव के लोग धार्मिक कार्य करते हैं। यहां के वृक्षों को कोई नहीं काट सकता है यहां पर निरंतर निगरानी के लिए दोनों गांव के लोग आते रहते हैं।

झरौली ग्राम से मलखान रैकवार ने बताया, "यहां के पेड़ों को 25 से 30 साल हो चुके हैं हमारे जो गुरुजी थे, उन्होंने वृक्ष लगाने के लिए बड़े बुजुर्गों को प्रेरणा दी, सभी बड़े बुजुर्गों ने समिति बनाई, वृक्षारोपण के बारे में सभी ने विचार किया सभी ने वृक्षों को लगाया, निरंतर उनकी निगरानी की। इसके बावजूद भी कोई वृक्षों को काटता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है हम सभी बनाए हुए नियमों के अनुसार यहां के सभी काम करते हैं।"

झरौली और मुँवार ग्राम निवासी न्याम सिंह लोधी ने कहा, "यहां पर सागौन, सेजा, छेलिया और कुछ पीपल के पेड़ भी लगे हैं। दोनों गांवों की सहमति से यहां पर काम होता है, यहां के वृक्षों की यदि कोई एक डगार भी तोड़ता है तो उसको 1 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता है यह संकल्प लिया गया है, इसलिए यहां पर कोई भी वृक्ष को काटता ही नहीं है। दोनों गांव के लोग मिलकर इस जंगल की रक्षा करते हैं।"

ग्राम झरौली मुवार निवासी जलान सिंह ने बताया झरौली मुवार की समिति बना कर के यहा पर पेड़-पौधे लगाए, यहा की भूमि लगभग 50 हेक्टेयर हैं। इस जंगल में पीपल, नीम, कुछ पेड़ सागौन के एवं छेलिया के पेड़ सहित अन्य प्रजातियों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ग्राम वाशियों द्वारा विचार किया गया है कि यहा पर एक मकान बना दिया जाये या कोई मंच सभी को बैठने के लिए बनना चाहिए।

■ ■

ग्राम वन समिति के भागीरथ प्रयास से बंजर पहाड़ी क्षेत्र में आई हरियाली

ग्राम वन समितियां वन विभाग के सहयोग से बिगड़े वनों को सुधारने के साथ ही उन्हें व्यवस्थित करने तथा बंजर व पहाड़ी क्षेत्र में नवीन पौधरोपण का कार्य कर रही हैं। वन समितियों द्वारा पहाड़ी व जंगली क्षेत्र में जल स्त्रोत का निर्माण भी कराया जा रहा है। इन सभी कार्यों में ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

रीवा जिले के मेहना वन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वन समिति इटार पहाड़ द्वारा एफपीओ योजना अंतर्गत 25 हेक्टेयर क्षेत्र में दस हजार से अधिक पौधे लगाए गए, जिसमें से अभी भी 70 से 80 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। जिनके कारण पहाड़ी बंजर जमीन हरी-भरी हो गई है। वन समिति के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर त्रिवेदी बताते हैं, "हमारी समिति द्वारा वन विभाग की लाभांश राशि द्वारा ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए बावली का निर्माण कराया गया। ग्रामीणों की मांग पर सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने 15 लाख रुपए की राशि स्टॉपडैम निर्माण के लिए प्रदान की, जिसके बन जाने से आसपास के क्षेत्र के किसान अपने खेतों में सिंचाई कर पा रहे हैं। वन समिति झिरिया नर्सरी भी संचालित कर रही है, जहां से अभी तक एक लाख पौधे विक्रय किए जा चुके हैं। इससे जो राशि प्राप्त होती है, वह श्रमिकों को भुगतान देने में मददगार होती है। वन समितियां वनों की सुरक्षा करने, अवैध कटाई, अवैध शिकार, अग्नि दुर्घटना तथा अवैध उत्खनन को रोकने के साथ वन क्षेत्रों का रखरखाव करती हैं, जिससे वन क्षेत्र हरा भरा रहे।"

इटार वन समिति के कार्यकारिणी के 14 सदस्य वन परिक्षेत्र अन्तर्गत प्राकृतिक पौधों एवं रोपित पौधों की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व निभाते हैं। वन मंडलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह, एसडीओ वन ऋषि मिश्रा, सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी महेन्द्रशरण त्रिपाठी व समिति के सचिव एवं वीटगार्ड अलिखेश पटेल का सहयोग वन समिति को मिलता है, जिसका परिणाम है कि पहाड़ी वंजर क्षेत्र हराभरा हो गया है। किसानों को सिंचाई का पानी व जल स्त्रोत बन जाने से पीने का पानी भी उपलब्ध हो रहा है।

■ ■

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

सफलता की कहानी

जिला - रीवा

वन समिति ने जन सहयोग से 20 हजार से अधिक वृक्षों को किया तैयार

मानव के जीवन चक्र में वनों और वनस्पतियों का बहुत महत्व है। पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण के लिए भी वनों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। इस उद्देश्य से वन विभाग द्वारा 1995 से संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की गईं। रीवा जिले के डभौरा रेंज में आदिवासी बहुल ग्राम गेंदुरहा में संयुक्त वन समिति ने जन सहयोग से वनों की सुरक्षा और संरक्षण का शानदार कार्य किया है। वन विभाग तथा वन समिति के लगातार प्रयासों से 20 हजार से अधिक हरे-भरे वृक्ष तैयार किए गए हैं। समिति ने 30 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को हरा-भरा बना दिया है। जिस स्थान पर छोटी झाड़ियों और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ हरे-भरे वृक्ष लहरा रहे हैं।

वन प्रबंधन तथा संरक्षण के संबंध में वन समिति के अध्यक्ष बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को गेंदुरहा में मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। समिति के अधिकांश सदस्य आदिवासी हैं जो वर्षों से आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। उन्हें प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण कराया गया। वन विभाग में गांव में हैण्डपंप तथा आदिवासी मोहल्ले में चबूतरे का निर्माण जैसे आस्थामूलक कार्य करके लोगों का विश्वास जीता। वन समिति ने वन विभाग के सहयोग से पूरे क्षेत्र में छोटे नालों पर कई बोल्डर चेक डैम बनाए। इनसे एक ओर मिट्टी का कटाव रुका वहीं दूसरी ओर पेड़-पौधों और वन्य प्राणियों के लिए पानी भी उपलब्ध हुआ।

वन समिति ने नए पौधे तैयार करने के साथ वन में मौजूद पुराने वृक्षों की देखभाल और सुरक्षा पर ध्यान दिया। आदिवासी परिवार अप्रैल और मई में महुआ बीनने जाते हैं। उनकी आमदनी का महुआ प्रमुख जरिया है। महुआ संग्रहण को व्यवस्थित तथा वनों को सुरक्षित करने का प्रयास समिति द्वारा किया गया। परिवारों को महुआ के पेड़ आवंटित कर दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा, देखभाल एवं उनसे मिलन वाले महुआ फूल पर आदिवासी परिवार का ही हक बनाए रखा गया। इससे महुआ बीनने के समय होने वाली आगजनी की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगी। वन समिति के सदस्यों की जागरुकता, आमजनता के सहयोग तथा वन विभाग की सक्रियता से वृक्षों की अवैध कटाई एवं अवैध उत्खनन पर भी पूरी तरह से रोक लगाने में समिति को सफलता मिली। गेंदुरहा वन समिति संयुक्त वन प्रबंधन का शानदार उदाहरण है।

मध्यप्रदेश वन विभाग के प्रयासों और वन ग्राम समिति की मेहनत से हो रही है वनों की बहाली

जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करने और वन क्षेत्र में विकास के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग माइक्रोप्लानिंग के माध्यम से कार्य कर रहा है। वनवासियों और स्थानीय समुदायों की जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम वन समितियों को इससे जोड़कर इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। स्थानीय समुदायों को नज़रअंदाज करके वनों की बहाली और विकास मुमकिन नहीं है। वनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं में स्थानीय समुदायों की जनभागीदारी जरूरी है। वन जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव को कम करने में जंगल सबसे सहायक सिद्ध होते हैं। जंगल अपने आप में ही एक अलग संसार को समेटे होते हैं। धरती की अमूल्य जैव विविधता को बचाए रखने के लिए भी इन जंगलों को बचाए रखना जरुरी है। यही वजह है कि ग्राम वन समितियों के सहयोग से जंगलों की बहाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों की ग्राम समितियों के प्रयासों से वन बहाली का मुश्किल कार्य संभव हो सका है। ऐसी ही एक ग्राम वन समिति है पश्चिमी मंडला वन प्रभाग की मनेरी ग्राम वन समिति। इस समिति का गठन 1996 में किया गया था। ग्राम वन समिति को 186.92 हेक्टेयर के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था। कम्पार्टमेंट संख्या 642 आरएफ अत्यधिक निम्नीकृत वन क्षेत्र है। यह वन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के आसपास का होने के कारण गंभीर जैविक दबाव में था। बावजूद इसके स्थानीय समुदायों ने अवैध कटाई और चराई के खिलाफ वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्किंग के स्टॉक मैपिंग के अनुसार योजना (वर्ष 2004-14) क्षेत्र वनस्पति से रहित था और आरडीएफ कार्य करने के लिए आवंटित किया गया था।

साल 2003-04 और 2005-06 के बीच आरडीएफ योजना के तहत इस क्षेत्र की बहाली का काम शुरु हुआ। ग्राम वन समिति मनेरी का नेतृत्व कर रही एक महिला सुश्री कल्लू बाई मार्को ने वन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए समुदाय को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम वन समुदाय के अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के चलते आज निर्धारित क्षेत्र वनों से बहाल हो गया है। इतना ही नहीं बीते दो सालों में समुदाय ने 3 हजार 526 सागौन और 31 ईंधन के ढेर की कटाई कर लाभ कमाया है। यह वन क्षेत्र जंगलों की बहाली के उद्देश्य से ही समुदाय को आवंटित किया गया था जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है।

मध्यप्रदेश के वनों की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है झाबुआ जिले की ग्राम वन समिति

मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 308245 वर्ग किमी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य मध्यप्रदेश है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30 प्रतिशत वनक्षेत्र है जो लगभग 94689 वर्ग किमी है। जिसकी देश के वन क्षेत्र में करीब 12.30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। प्रदेश की लगभग 21 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय की है जो ज्यादातर वन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं। जनजातीय समुदाय की आजीविका में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में वनों के संरक्षण, प्रबंधन और वनों की बहाली के लिए ग्राम वन समितियों के साथ जनभागीदारी से कार्य किया जा रहा है। इन वन समितियों की भागीदारी से वन क्षेत्रों को बहाल किया जा रहा है। इस मुहिम से वनों पर आश्रित समुदायों के आजीविका बढ़ने के साथ ही जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। हालांकि वनों की कटाई एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है। वनों के कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन बड़ी जलवायु संबंधी समस्याएं पैदा करता है और पहले से मौजूद समस्याओं को गंभीर करता है। ऐसे में वनों की बहाली ही प्रभावी उपाय है। स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबंधन और उनकी बहाली में शामिल करना जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक उचित और स्थायी तरीका है। इसी दिशा में कार्य करते हुए मध्यप्रदेश वन विभाग के प्रयासों से वनों की बहाली की जा रही है।

स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गठित झाबुल जिले की बड़ी नाल्दी की ग्राम वन समिति ने आवंटित वन क्षेत्र को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1995 में इस गठित इस समिति को 192 हेक्टेयर खाली वन क्षेत्र आवंटित किया गया था। बड़ी नाल्दी ग्राम वन समिति के सदस्यों और ग्रामीणों द्वारा सालों किये गये प्रयास से आवंटित वन क्षेत्र को बहाल कर वहां वनों को पुन: स्थापित किया गया है। वन विभाग और ग्राम वन समितियों के इन संयुक्त प्रयासों से निरंतर प्रदेश का वन क्षेत्र बढ़ रहा है जिससे न सिर्फ जलवायु संतुलन में मदद मिल रही है बल्कि जनजाति समुदाय की वनोपज पर निर्भर आजीविका में भी बढ़ोत्तरी हुई है। मध्यप्रदेश वन विभाग की दृढ़ इच्छाशक्ति और वन ग्राम समिति के अथक

प्रयासों से वनों के संरक्षण और विकास की दिशा में किये जा रहे कार्य प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय हैं।

जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करने और वन क्षेत्र में विकास के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग माइक्रोप्लानिंग के माध्यम से कार्य कर रहा है। वनवासियों और स्थानीय समुदायों की जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम वन समितियों को इससे जोड़कर इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। स्थानीय समुदायों को नज़रअंदाज करके वनों की बहाली और विकास मुमकिन नहीं है, वनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं में स्थानीय समुदायों की जनभागीदारी जरुरी है। वन जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव को कम करने में जंगल सबसे सहायक सिद्ध होते हैं। जंगल अपने आप में ही एक अलग संसार को समेटे होते हैं। धरती की अमूल्य जैव विविधता को बचाए रखने के लिए भी इन जंगलों को बचाए रखना जरुरी है। यही वजह है कि ग्राम वन समितियों के सहयोग से जंगलों की बहाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों की ग्राम समितियों के प्रयासों से वन बहाली का मुश्किल कार्य संभव हो सका है। ऐसी ही एक ग्राम वन समिति है पश्चिमी मंडला वन प्रभाग की मनेरी ग्राम वन समिति। इस समिति का गठन 1996 में किया गया था। ग्राम वन समिति को 186.92 हेक्टेयर के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था।

कम्पार्टमेंट संख्या 642 आरएफ अत्यधिक निम्नीकृत वन क्षेत्र है। यह वन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के आसपास का होने के कारण गंभीर जैविक दबाव में था। बावजूद इसके स्थानीय समुदायों ने अवैध कटाई और चराई के खिलाफ वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्किंग के स्टॉक मैपिंग के अनुसार योजना (वर्ष 2004-14) क्षेत्र वनस्पति से रहित था और आरडीएफ कार्य करने के लिए आवंटित किया गया था।

साल 2003-04 और 2005-06 के बीच आरडीएफ योजना के तहत इस क्षेत्र की बहाली का काम शुरु हुआ। ग्राम वन समिति मनेरी का नेतृत्व कर रही एक महिला सुश्री कल्लू बाई मार्को ने वन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए समुदाय को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम वन समुदाय के अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के चलते आज निर्धारित क्षेत्र वनों से बहाल हो गया है। इतना ही नहीं बीते दो सालों में समुदाय ने 3 हजार 526 सागौन और 31 ईंधन के ढेर की कटाई कर लाभ कमाया है। यह वन क्षेत्र जंगलों की बहाली के उद्देश्य से ही समुदाय को आवंटित किया गया था जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है।

■ ■

संयुक्त वन प्रबंधन का कमाल

240 हेक्टेयर में लहरा रहे वृक्ष

सिंगरौली की सतपहरी वन समिति ने 10 साल में लगाए दो लाख से अधिक पौधे

वनों का विदोहन, प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए वन विभाग द्वारा संयुक्त वन समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने कई वन क्षेत्रों में शानदार कार्य करते हुए वनों के संरक्षण और संवर्धन में सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। सिंगरौली जिले की सतपहरी ग्राम वन समिति ने 10 वर्षों में 240 हेक्टेयर वन क्षेत्र को हरा-भरा बना दिया है। वन विभाग के सहयोग से समिति के सदस्यों ने दो लाख 20 हजार से अधिक यूकेलिप्टस के पौधे रोपित किए हैं। नए पौधे रोपित करने के साथ-साथ वन क्षेत्र के पुराने वृक्षों का भी सरंक्षण किया गया।

वन समिति ने वन विभाग के सहयोग से चरणबद्ध ढंग से वृक्षारोपण किया। अब तक 240 हेक्टेयर क्षेत्र में हरे-भरे वृक्ष लहरा रहे हैं। ग्राम वन समिति सतपहरी में शामिल ग्रामों में सतपहरी, बम्हनी और गौरवा में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। वन प्रबंधन और वृक्षारोपण से समिति को प्रथम वर्ष एक लाख 6 हजार 902 रुपए की आय प्राप्त हुई। समिति द्वारा व्यवस्थित तरीके से यूकेलिप्टिस पौधों का चरणबद्ध विदोहन किया जा रहा है। इससे समिति को इस वर्ष चार लाख 6 हजार रुपए की आय होने का अनुमान है। ग्राम वन समिति सतपहरी जन भागीदारी से वन प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

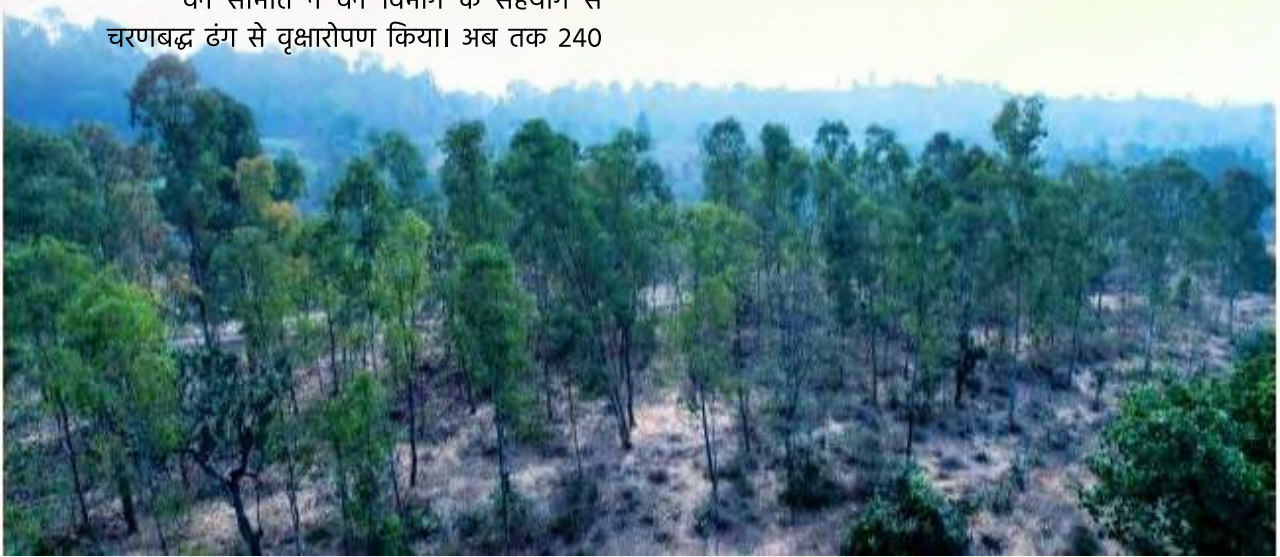

छपरा के 124 हेक्टेयर क्षेत्र में पुर्नजीवित हुआ जंगल

कटनी जिले के बहोरीबंद की छपरा ग्राम वन समिति ने बिगड़े वन के सुधार में संयुक्त वन प्रबंधन की शानदार नजीर पेश कर 124 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल को पुर्नजीवित कर दिया है। कुछ साल पहले तक वीरान हो चुकी इस पहाड़ी में अब सघन वनीकरण के लिए बाद यहां की जैव विविधता समृद्ध हुई है।

ग्राम वन समिति छपरा ने जब मानवीय गतिविधियों और पहाड़ी पर मवेशी चराने से लोगों को रोका तो पौधे का प्राकृतिक पुनरूद्भव हुआ। साथ ही यहां कुछ सालों में सघन पौधरोपण का कार्य भी किया गया। रोपे गए पौधे अब बड़े पेड़ों बदल गए हैं। समिति के सदस्य और ग्रामीणजन भी अब अपने बच्चों को इस उम्मीद से जंगल के महत्व से परिचित करा रहे हैं, ताकि वे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी देखभाल करें।

वनमंडलाधिकारी आरसी विश्वकर्मा ने बताया कि वन समिति के सदस्यों के निस्तार के लिए 17-18 सौ क्विंटल जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता जंगल में गिरी-पड़ी सूखी लकड़ी से पूरी हो जाती है। बीते साल सदस्यों को निस्तार हेतु 965 नग बल्लियां और 22 नग जलाऊ लकड़ी का चट्टा समिति को दिया गया। साथ ही बल्लियों की बिक्री से प्राप्त करीब 97 हजार रुपये की राशि को समिति के खाते में जमा किया गया है। इसके अलावा वनोत्पाद व वनोपज के संग्रह व विक्रय से भी आय अर्जित हो रही है। श्री विश्वकर्मा बताते हैं कि सघन वन हो जाने की वजह से अब यहां तेंदुआ, जंगली सूअर, सियार, मोर और चीतल आदि की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।

■ ■

वीरपुरा वन समिति के प्रयासों से क्षेत्र हुआ हरा-भरा

दक्षिण वन मण्डल सागर के अंतर्गत आमेट वन क्षेत्र की ग्राम वन समिति वीरपुरा ने बिगड़े वन क्षेत्र के सुधार में सराहनीय कार्य किया है। समिति की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सदस्यों की मेहनत से आवंटित क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों में वनावारण बढ़ा और हरा-भरा हुआ है। वर्तमान में आवंटित क्षेत्र में वनां की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके साथ ही समिति अपने क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों में भी रुचि लेकर कार्य कर रही है। संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विभाग के संयुक्त रुप से कड़ी मेहनत द्वारा बिगड़े वनों को सुधारा जा सका है।

समिति के अध्यक्ष श्रीमती इमरती बाई और उपाध्यक्ष सुमन दुबे निरन्तर रुचि लेकर कार्य कर कर रही हैं। समिति द्वारा वन क्षेत्र के लोगों के उपयोग के लिये चौपाल चबूतरा निर्माण कराया गया। पषुओं के पानी के लिये हौदी का निर्माण कराया गया। समिति ने कुआ की साफ-सफाई एवं मरम्मत कराई। क्षेत्र में स्वास्थ षिविरि का आयोजन कर लोगों का स्वास्थ परीक्षण भी कराया। समिति के अच्छे कार्यों तथा वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के सतत प्रयास से वर्तमान में बिगड़े वन अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। प्राकृतिक रहवास की निरंतर सुरक्षा तथा बढ़ते वनावरण के कारण इन क्षेत्रों में वन्याप्राणियों की संख्या में निरंतर इजाफा देखने में आ रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

वन समितियों का सम्मेलन

Channels	Duration (M:S)
ZEE MP	61.04
NEWS 18 MPCG	56.12
IBC24	57.48
NEWS STATE	49.08
BANSAL	66.44
INDIA NEWS	71.50
IND24	71.30
SAHARA	14.41
INH24X7	66.18
ANAADI TV	70.44
SADHNA	65.25
NEWS WORLD	83.11
DNN	76.58
DDMP	69.43
NEWS 24 MPCG	55.07

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज

सोशल मीडिया कवरेज

वन समितियों का सम्मेलन

विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पर सीधा प्रसारण

वन समितियों का सम्मेलन

सोशल मीडिया कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

@CMMadhyaPradesh (Twitter)

सोशल मीडिया कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

@CMMadhyaPradesh (Facebook)

CM Madhya Pradesh

वन समितियों को काष्ठ व बांस के लाभांश की 55 करोड़ की राशि वितरित की गई। 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों के बैंक खातों में 68 करोड़ रु सीधा बिचौलियों के बगैर गया है। 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन किया है केंद्रीय गृह मंत्री श्री Amit Shah
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

CM Madhya Pradesh

पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे जनजातीय भाइयों को बनाने का कार्य कर रही है। पहली बार वनों से होने वाली कमाई का 20 प्रतिशत लाभांश वन समिति के हाथ में सौंपकर उन्हें सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्री श्री Amit Shah
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

CM Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में जिन गरीब भाई-बहनों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। उनको मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत रहने की जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार करोड़ रु बजट में रखे गये हैं: CM
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

CM Madhya Pradesh

तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का कार्य शुरू किया गया है। आज 125 करोड़ रु 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। तेंदूपत्ता तुड़वाई के अभी तक 250 रु प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे अब से 300 रु प्रति 100 गड्डी दिए जाएंगे: CM
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

CM Madhya Pradesh

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे जनजातीय भाई-बहनों ने वनों से केवल लाभ प्राप्त नहीं किया बल्कि वनों की जिंदगी को भी संजाने संवारने का भी कार्य किया है। प्रदेश में हरियाली लाने का कार्य किया है: CM
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

CM Madhya Pradesh

केंद्रीय गृह मंत्री श्री Amit Shah जी एवं मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने वन समितियों को सांकेतिक लाभांश और संग्राहकों को तेंदूपत्ता के लाभांश का वितरण किया।
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

सोशल मीडिया कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

@CMMadhyaPradesh (Instagram)

cmmadhyapradesh

1,013 views

cmmadhyapradesh केंद्रीय गृह मंत्री श्री @amitshahofficial जी एवं मुख्यमंत्री श्री @chouhanshivrajsingh ने वन समितियों को सांकेतिक लाभांश और संग्राहकों को तेंदूपत्ता के लाभांश का वितरण किया।
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

cmmadhyapradesh

136 views

cmmadhyapradesh मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे जनजातीय भाई-बहनों ने वनों से केवल लाभ प्राप्त नहीं किया बल्कि वनों को जिंदगी को भी संजाने संवारने का भी कार्य किया है। प्रदेश में हरियाली लाने का कार्य किया है: CM
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

cmmadhyapradesh

58 likes

cmmadhyapradesh भोपाल में केंद्रीय गृहमंत्री माननीय श्री @amitshahofficial जी ने मुख्यमंत्री श्री @chouhanshivrajsingh एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रिमोट का बटन दबाकर वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर वन ग्रामों को शुभकामनाएं दी।

#वनोपज_से_समृद्धि_MP

cmmadhyapradesh

409 views

cmmadhyapradesh पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे जनजातीय भाइयों को बनाने का कार्य कर रही है। पहली बार वनों से होने वाली कमाई का 20 प्रतिशत लाभांश वन समिति के हाथ में सौंपकर उन्हें सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है: केंद्रीय गृह मंत्री श्री @amitshahofficial
#वनोपज_से_समृद्धि_MP

सोशल मीडिया कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

@CMMadhyaPradesh (Koo)

सोशल मीडिया कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

@JansamparkMP
@minforestmp

सोशल मीडिया कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

डिजिटल मीडिया कवरेज

डिजिटल मीडिया कवरेज

इन-इवेंट

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

डिजिटल मीडिया कवरेज

इन-इवेंट

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

THE WEEK

Amit Shah lauds CM Chouhan in Bhopal; tribal outreach, poll strategy in focus during his visit

Chouhan's scheduled meet with PM on Saturday elicits reaction from Congress

By Sravani Sarkar Updated: April 22, 2022 21:39 IST

Union Home Minister Amit Shah examines the weapons on display during the inaugural session of the 48th All India Police Science Congress at Central Academy of Police Training, in Bhopal | PTI

Tribal outreach, discussion of poll strategy and enthusiastic display of political strength by the ruling BJP marked the nine-hour-long visit of Union Home Minister Amit Shah to Bhopal on Friday.

Shah, considered the second most powerful leader of the party in the country, also lauded the leadership of Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan. Shah mentioned that the state had achieved highest economic growth (19.1 per cent) under Chouhan and that his move to make tribals 'the owner of forests' was a first in the country and worth emulation.

The Union home minister's appreciation came during a programme held to distribute bonus amounts to tendu leaf collectors – majority of them forest dwellers/tribals at Jamboree ground in Bhopal. Hundreds of tribal people attended the programme.

Shah said the BJP government in MP has decided to hand over 20 per cent of all earnings from forests to community-based forest committees, which was a revolutionary move to give ownership of forest resources to tribal people. He also mentioned that 827 forest villages would be converted to revenue villages to benefit the tribal people.

Chouhan said on the occasion that the forest, land and water belonged to the local tribals and they would only save it. "We are handing over the forests to you. The forest department will only assist you. From the sale of forest wood, 20 per cent will go to the tribals. The rate of tendu leaves collection per 100 stacks will be hiked to Rs 300 from Rs 250," the CM announced.

हिन्दुस्तान

union home minister amit shah bhopal tribal program madhya pradesh

livehindustan.com/madhya-pradesh/story-union-home-minister-amit-shah-bhopal-tribal-program-madhya-pradesh-6327516.html

22 अप्रैल 2022

आदिवासियों पर निगाह, 2023 पर निशाना? गृहमंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे से क्या संदेश

लाइव हिंदुस्तान,भोपालDeepak

Fri, 22 Apr 2022 06:20 PM

इस खबर को सुनें

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के जंबूरी मैदान में आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पिछले सात महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। इन सात महीनों के भीतर पीएम मोदी भी बीते नवंबर में भोपाल जा चुके हैं। इसके अलावा मोदी वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए भी जुड़ चुके हैं। आखिर भाजपा के तमाम बड़े नेता आदिवासी समुदाय पर क्यों अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की गणित...

सात महीने में दूसरी बार

गौरतलब है कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा पूरी तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि भाजपा के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। खुद गृहमंत्री अमित शाह भी सात महीने में दूसरी बार यहां पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब सितंबर 2021 में शाह जबलपुर आए थे तब भी वह आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब वह गोंडवाना साम्राज्य के शहीद राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर हुए आयोजन में शामिल हुए थे। वहीं 2021 के नवंबर में पीएम मोदी भी आदिवासियों से जुड़ कार्यक्रम में ही भोपाल पहुंचे थे।

आदिवासी वोटों की गणित

असल में मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट चुनाव में हार-जीत का अंतर पैदा करते हैं। दो करोड़ से ज्यादा आदिवासी प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों पर प्रभावी भूमिका में हैं। यानी इन सीटों पर आदिवासी वोट हार या जीत तय कर सकते हैं। इसमें भी खास बात यह है कि इन 87 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। यही वजह है कि भाजपा का पूरा फोकस आदिवासी वोट बैंक पर

THE TIMES OF INDIA

Shivraj has made special contribution to transform MP into a developing state: Amit Shah

timesofindia.indiatimes.com/india/shivraj-has-made-special-contribution-to-transform-mp-into-a-developing-state-amit-shah/articleshow/91012998.cms

BHOPAL: Union home and cooperatives minister Amit Shah praised chief minister Shivraj Singh Chouhan saying that he has made a "special contribution in transforming Madhya Pradesh into a developing state from a BIMARU (pun on sick) one".

Before the commencing of the 48th All India Police Science Congress meet organised at Central Police Training Academy (CAPT) in Bhopal, Shah and Chouhan paid floral tributes and garlanded martyrs at Shaheed Memorial on the premises. Plantation was also done at all religious places on the campus, and an exhibition of new equipment was inaugurated on the occasion of All India Police Science Congress in the academy.

Union minister Shah and CM Chouhan released five books. These include Compendium on All India Police Science Congress, 45th issue of Police Science magazine, Data on Police Organization 2021, Best Practices on Smart Policing and National Syllabus for Directly Recruited Sub Inspectors.

Shah said that the books which have been released should be studied by the police officers in all the states. Their summary should be made available to every officer of the SP level. It is necessary to convey the findings of various studies contained in the books to every officer-employee of the police.

Chouhan, while welcoming Shah on behalf of the people of the state, said that it is a matter of good fortune that All India Police Science Congress is being held in Bhopal.

Chouhan quoted Gita, saying, "Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam", adding it is the duty of the police to protect good people and take action against the wicked.

"In Covid-19, the police presented exemplary examples of service. The police have to tackle challenges like de-addiction campaigns, safety of daughters and control of cyber crime. Therefore, training of the police, facilities for scientific investigation, availability of tools of investigation and every possible use of forensic science is the need of the hour. I am sure that the representatives of the police forces attending the Police Science Congress, representatives of scientific universities, will discuss various topics and challenges and present their solutions," Chouhan said, welcoming all the delegates who came to

Funds for tribal welfare have increased under Modi govt: Amit Shah in MP

hindustantimes.com/cities/bhopal-news/funds-for-tribal-welfare-have-increased-under-modi-govt-amit-shah-in-mp-101650657518914.html
April 23, 2022
bhopal news

- Union minister Amit Shah was speaking at 'Van Samiti Sammelan', a programme where bonus was distributed to collectors of forest produce such as tendu leaves and forest societies when he made the statement.

Union home minister Amit Shah. (ANI)

By Shruti Tomar, Bhopal

Prime Minister Narendra Modi is committed to the welfare of tribals and has allocated ₹78,000 crore for various schemes and programmes for the community ever since he assumed office in 2014, Union home minister Amit Shah said on Friday.

"This is a government of the poor, Scheduled Tribes, Dalits and Backward Classes. During the Congress government's time, only ₹21,000 crore was provided for the welfare of (tribal) people, but after Prime Minister Modi came to power in 2014, funds for tribal uplift were enhanced to ₹78,000 crore," Shah said.

The Union minister was speaking at 'Van Samiti Sammelan', a programme where bonus was distributed to collectors of forest produce such as tendu leaves and forest societies when he made the statement.

Tribals constitute more than 21% of Madhya Pradesh's population. This was the second tribal outreach by Shah in just over six months in the BJP-ruled state where assembly elections are due in 2023.

THE TIMES OF INDIA

Modi government increased funds for tribal welfare: Amit Shah

timesofindia.indiatimes.com/india/modi-government-increased-funds-for-tribal-welfare-amit-shah/articleshow/91005504.cms

PTI / Apr 22, 2022, 17:54 IST

Union home minister Amit Shah

BHOPAL: Prime Minister Narendra Modi increased the allocation of funds for the welfare of tribal communities drastically after coming to power, Union home minister Amit Shah said on Friday.

He was speaking at 'Van Samiti Sammelan', a program where bonus was distributed to collectors of forest produce such as Tendu leaves. "This is a government of the poor, Scheduled Tribes, dalits and backward classes. During Congress government's time, only Rs 21,000 crore were provided for the welfare of (tribal) people, but after Modi came to power in 2014, it has been enhanced to Rs 78,000 crore," Shah said.

He also unveiled a plaque announcing the change of status of 827 'forest villages' into 'revenue villages'. There was a demand that these areas be declared revenue villages to ensure their development as there are restrictions on undertaking projects in forest areas. Terming the decision as historic, the Union minister said that it fulfilled a long-pending demand.

The Modi government has resolved to construct houses for each and every individual by 2022, Shah further said. The Madhya Pradesh government has also decided to provide 20 per cent bonus to forest societies, he noted. Scheduled Tribes account for 21 per cent of Madhya Pradesh's population. Several other Union ministers including Jyotiraditya Scindia, Prahlad Patel, Faggan Singh Kulaste and L Murugan besides state chief minister Shivraj Singh Chouhan, his cabinet colleagues Vijay Shah, Bhupendra Singh, Narottam Mishra and Vishwas Sarang, BJP general secretary Kailash Vijaywargiya and state BJP chief VD Sharma were among those present.

Speaking at the function earlier, Chouhan highlighted the steps taken by his government for the welfare of tribal population, especially the decision to convert 827 out of 925 forest villages into revenue ones.

नईदुनिया

Amit Shah in Bhopal: भोपाल में अमित शाह ने कहा, मध्य प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाना बड़ा फैसला

naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-amit-shah-in-bhopal-amit-shah-said-in-bhopal-a-big-decision-to-make-revenue-village-in-madhya-pradesh-7476630

April 22, 2022

Amit Shah in Bhopal: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, पहली बार कोई राज्य सरकार जनजाति भाइयों को जंगल का मालिक बना रही है।

Updated: | Fri, 22 Apr 2022 05:22 PM (IST)

Amit Shah in Bhopal: भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है। इसका 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को आप साकार करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज एक ही बार में 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों को परिवर्तन किया है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का फैसला है। राज्य में हमारा भी हिस्सा है इस अधिकार के साथ आज यहां से जा रहे हैं। 2022 के अंत के पहले अपना घर देने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, हर घर में बिजली पहुंचाने, शौचालय बनाने का काम हो गया है। हर घर में जल, नल से पहुंचाने का प्रयोग शुरू हो गया है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि दस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200 प्रतिशत की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। ये रुकने वाले कार्य नहीं है। जितने भी कार्य जनजाति भाइयों के लिए हमने घोषित किए हैं वे सभी पूरे होंगे।

price inflation of Edible oil: तीन साल में दोगुने हुए खाद्य तेलों के दाम, आमजन पर पड़ रही महंगाई की मार

तेंदूपत्ता तुड़वाने के लिए अब 300 रुपये प्रति गड्डी मिलेंगे

कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता तुड़वाने के अभी ढाई सौ रुपए प्रति सौ गड्डी दिए जाते थे अब वह बढ़ाकर तीन सौ रुपए प्रति सौ गड्डी किए जाएंगे। जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे वे एक-एक करके जमीन पर उतार रहे हैं और गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। 89 जनजतीय ब्लाक में राशन की गाड़ी भेजने कहा था, मुझे कहते हुए खुशी है वह राशन बंटना अधिकांश स्थानों पर प्रारंभ हो गया है।

सीएम शिवराज ने कहा कि पेसा एक्ट क्रमश: मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, मप्र में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी, उसकी आय आप ही प्राप्त करोगे। जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी, मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा।

उन्होंने कहा कि अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज 125 करो

KRISHI JAGRAN

VFC Helps Forest People in Madhya Pradesh to Stop Tree Felling, Reclaims Forests

krishijagran.com/featured/vfc-helps-forest-people-in-madhya-pradesh-to-stop-tree-felling-reclaims-forests

VFC Helps Forest People in Madhya Pradesh to Stop Tree Felling, Reclaims Forests

The government's sustainable approach to protecting forests through the involvement of the local community has led to the full stocking of the area.

Kallu Bai Marko, a representative of Maneri Village Forest Committee (VFC) in the West Mandla Forest Division of Madhya Pradesh, has been toiling hard for years with a dream to provide sustainable livelihoods for the forest-dependent communities at the local level.

The plan consists of ecosystem restoration to achieve the highest level of recovery for biodiversity and human well-being. She was fortunate to join VFC Maneri, constituted in the year 1996, which was entrusted with the management of 186.92 hectares of the highly degraded forest area of compartment number 642 RF.

Her significant role in mobilizing the community for the protection and management of the forest area put a stop to the illicit felling of trees and uncontrolled grazing. The tireless efforts and commitment of the community brought them success. VFC Maneri has harvested 3526 Teak poles and 31 fuel stacks in the last few years. The government's sustainable approach to protecting forests through the involvement of the local community has led to the full stocking of the area. Due to significant improvement in the stock, the area was allotted to the 'Improvement Working Circle' in the subsequent working plan (Plan of 2016-26).

Cool environment for good health of dogs is essential in the summer: Veterinary Expert

Summer is good period for you and your dog to spend time outdoors exercising and having fun. But it is...

Communities have played an integral role in restoring large tracts of degraded forest areas in the state. To encourage these communities, the Government of Madhya Pradesh decided to reward their efforts. For participatory, scientific, and sustainable management of the forests, a target of 5000 micro-plans has been set under the 'Atmanirbhar Madhya Pradesh' campaign, till the year 2022-23.

The forest produce obtained from silviculture operations is being given to these communities. This action has positively motivated people to participate in the effective management of the forests.

आउटलुक

मध्यप्रदेश वन विभाग के प्रयासों और वन ग्राम समिति की मेहनत से हो रही है वनों की बहाली

outlookhindi.com/country/india/forests-are-being-restored-due-to-the-efforts-of-madhya-pradesh-forest-department-and-the-hard-work-of-van-gram-samiti-66811

आउटलुक ब्यूरो

जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करने और वन क्षेत्र में विकास के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग माइक्रोप्लानिंग के माध्यम से कार्य कर रहा है। वनवासियों और स्थानीय समुदायों की जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम वन समितियों को इससे जोड़कर इस दिशा में कार्य हो रहे हैं।

स्थानीय समुदायों को नज़रअंदाज करके वनों की बहाली और विकास मुमकिन नहीं है। वनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं में स्थानीय समुदायों की जनभागीदारी जरूरी है।

वन जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव को कम करने में जंगल सबसे सहायक सिद्ध होते हैं। जंगल अपने आप में ही एक अलग संसार को समेटे होते हैं। धरती की अमूल्य जैव विविधता को बचाए रखने के लिए भी इन जंगलों को बचाए रखना जरुरी है। यही वजह है कि ग्राम वन समितियों के सहयोग से जंगलों की बहाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों की ग्राम समितियों के प्रयासों से वन बहाली का मुश्किल कार्य संभव हो सका है। ऐसी ही एक ग्राम वन समिति है पश्चिमी मंडला वन प्रभाग की मनेरी ग्राम वन समिति। इस समिति का गठन 1996 में किया गया था। ग्राम वन समिति को 186.92 हेक्टेयर के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था। कम्पार्टमेंट संख्या 642 आरएफ अत्यधिक निम्नीकृत वन क्षेत्र है। यह वन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के आसपास का होने के कारण गंभीर जैविक दबाव में था। बावजूद इसके स्थानीय समुदायों ने अवैध कटाई और चराई के खिलाफ वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्किंग के स्टॉक मैपिंग के अनुसार योजना (वर्ष 2004-14) क्षेत्र वनस्पति से रहित था और आरडीएफ कार्य करने के लिए आवंटित किया गया था।

साल 2003-04 और 2005-06 के बीच आरडीएफ योजना के तहत इस क्षेत्र की बहाली का काम शुरू हुआ। ग्राम वन समिति मनेरी का नेतृत्व कर रही एक महिला सुश्री कल्लू बाई मार्को ने वन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए समुदाय को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम वन समुदाय के अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के चलते आज निर्धारित क्षेत्र वनों से बहाल हो गया है। इतना ही नहीं बीते दो सालों में समुदाय ने 3 हजार 526 सागौन और 31 ईंधन के ढेर की कटाई कर लाभ कमाया है। यह वन क्षेत्र जंगलों की बहाली के उद्देश्य से ही समुदाय को आवंटित किया गया था जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है।

नईदुनिया

इंदौर जिले की ग्राम वन समिति नाहर झाबुआ ने अवैध कटाई से बचा रखा है दो हजार हेक्टेयर का जंगल

naidunia.com/madhya-pradesh/indore-nahar-jhabua-the-village-forest-committee-of-indore-district-has-saved-two-thousand-hectares-of-forest-from-illegal-harvesting-7475065

April 21, 2022

ग्राम वन समितियों ने वनों को बढ़ाने और उनकी सुरक्षा के लिए अनूठी मिसाल पेश की है। इंदौर जिले में कुल 116 समितियां हैं।

Publish Date: | Thu, 21 Apr 2022 04:52 PM (IST)

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। इंदौर जिले में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गठित की गई ग्राम वन समितियां बेहतर कार्य कर रही हैं। अनेक ऐसी समितियां हैं जिन्होंने वनों को बढ़ाने और वनों की सुरक्षा के लिए अनूठी मिसाल पेश की हैं। जिले की वन समिति नाहर झाबुआ ने दो हजार हेक्टेयर का वन क्षेत्र बचा रखा है। पहले यहां अवैध कटाई की कई घटनाएं होती थी, मगर अब इन पर रोक लगी है।

वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एके श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर जिले में कुल 116 ग्राम वन समितियां वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। इनके माध्यम से वनों की सुरक्षा और वन क्षेत्र बढ़ाने में मदद भी मिल रही है। इंदौर जिले की ग्राम वन समिति शिवनी (गढ़ी) ने वन क्षेत्र बढ़ाने में बेहतर सहयोग प्रदान किया है। गढ़ी क्षेत्र में लगभग साढ़े 26 हेक्टेयर में 32 हजार 150 पौधे लगाए गए। वन समितियों की लगातार देखभाल से पौधों को जीवित रखने और उन्हें बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके फलस्वरूप लगाए गए पौधों में से लगभग 26 हजार पौधे पूर्ण रूप से जीवित और सुरक्षित हैं। इस तरह पौधों के जीवित रहने का प्रतिशत 80 से अधिक है। यह उपलब्धि बेहतर मानी जाती है।

हर माह होते थे 10 से 15 प्रकरण - इसी तरह वन क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए नाहर झाबुआ की वन समिति द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में दो हजार से अधिक हेक्टेयर का वन क्षेत्र है। आज से दस वर्ष पूर्व बड़ी संख्या में वन को नुकसान पहुंचता था। वनों की अवैध कटाई होती थी। उस वक्त दस से 15 प्रकरण हर माह अवैध कटाई के दर्ज होते थे। वन विभाग के अमले द्वारा वन समिति को सक्रिय किया गया। 35 ग्रामीणों को लेकर वन समिति बनाई गई। इनका बेहतर सहयोग मिलने लगा। इस समिति के वर्तमान में रूप सिंह बानिया अध्यक्ष हैं। बताया गया कि वन समिति के सक्रिय सहयोग से प्रकरणों में साल दर साल कमी आती गई। वर्तमान में माह में अब एक या दो ही छोटे-छोटे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। वन समितियों का सहयोग बेहद मददगार साबित हो रहा है।

अमर उजाला

Khushkhabar: मध्य प्रदेश में वन ग्राम समितियों ने दो साल में ही हासिल कर लिए अपने लक्ष्य, कटाई रोकी, हरियाली बढ़ाई

amarujala.com/madhya-pradesh/khushkhabar-in-madhya-pradesh-forest-village-committees-achieved-their-goals-in-two-years-stopped-harvesting-increased-greenery

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 21 Apr 2022 04:43 PM IST

मध्य प्रदेश में वनों को बचाने में ग्राम वन समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीते दो सालों में ही इन समितियों ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लाभ अर्जित किया है।

बड़ी नाल्दी वन ग्राम समिति झाबुआ। - फोटो : अमर उजाला

लगातार कटते जंगलों से दुनियाभर का वातावरण प्रभावित हो रहा है। वनों को बचाना वर्तमान दौर में सबसे बड़ी चुनौती है। देश के दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30 फीसदी हिस्सा वनों से घिरा है, जो प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 94689 वर्ग किमी है। मध्य प्रदेश देश के वन क्षेत्र में करीब 12.30 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। प्रदेश में वनों को बचाने में आदिवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश की लगभग 21 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय की है जो ज्यादातर वन क्षेत्रों के आसपास रहती है और अपनी आवश्यकताओं रोजी-रोजी के लिए इन्ही वनों पर आश्रित है। आइए विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर हम आपको प्रदेश की कुछ ऐसी ही ग्राम वन समितियों के बारे में बताते हैं जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण, प्रबंधन और वनों की बहाली के लिए ग्राम वन समितियों के साथ जनभागीदारी से कार्य किया जा रहा है। इन वन समितियों की भागीदारी से वन क्षेत्रों को बहाल किया जा रहा है। इस मुहिम से वनों पर आश्रित समुदायों की आजीविका बढ़ने के साथ ही जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में वनों के कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन व जलवायु संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में पर्यावरण संतुलन और समस्याओं को सुलझाने के लिए वनों की बहाली ही प्रभावी उपाय है। स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबंधन और उनकी बहाली में शामिल करना जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक उचित और स्थायी तरीका है। इस दिशा में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रयासों से वनों की बहाली की जा रही है।

स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गठित झाबुल जिले की बड़ी नाल्दी की ग्राम वन समिति ने आवंटित वन क्षेत्र को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1995 में गठित इस समिति को 192 हेक्टेयर खाली वन क्षेत्र आवंटित किया गया था। बड़ी नाल्दी ग्राम वन समिति के सदस्यों और ग्रामीणों के प्रयासों से आवंटित वन क्षेत्र को बहाल कर वहां वनों को पुन: स्थापित किया गया है। वन विभाग और ग्राम वन समितियों के इन संयुक्त प्रयासों से निरंतर प्रदेश का वन क्षेत्र बढ़ रहा है, जिससे न सिर्फ जलवायु संतुलन में मदद मिल रही है बल्कि जनजाति समुदाय की वनोपज पर निर्भर आजीविका में भी बढ़ोत्तरी हुई है। मध्य

प्रिंट मीडिया कवरेज

पोस्ट-इवेंट कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

Print Media

मिशन-2023 • दो घंटे चली बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा नेताओं को बताया अगले विधानसभा-लोकसभा चुनाव का एजेंडा

राममंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी : शाह

ड्राफ्ट तैयार हो रहा, जल्द लागू करेगी केंद्र सरकार

जंबूरी में विपक्ष पर मौन, लेकिन भाजपा की बैठक में शाह बोले- अगले चुनाव से पहले राहुल हो जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, चिंता मत करना, कांग्रेस और नीचे जाएगी

शाह की बड़े मुद्दों पर दो टूक

चुनावी मोड... 2 करोड़ की आबादी को बड़ा अधिकार

मप्र में आदिवासी ही जंगल के मालिक

827 वन ग्राम अब राजस्व ग्राम बने, वहां सड़क, स्कूल, अस्पताल सब बनेंगे : शिवराज

हेलिकॉप्टर उड़ नहीं सका तो सड़क से एयरपोर्ट गए शाह

हरिभूमि

haribhoomi.com

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा- इसका पूरा श्रेय सीएम शिवराज सिंह को

वनोपज से समृद्धि

देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा पहला राज्य जहां आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया

1 इस सम्मेलन में शाह को सुनने के लिए प्रदेश के कोने-कोने से करीब एक लाख के आसपास वनवासी भोपाल आए हुए थे। 31 जिलों में शाह और शिवराज दोनों ने दिया भाषण

2 जंबूरी मैदान पर प्रदेश भर के वन समितियों के सम्मेलन में शाह व सीएम के हाथों 55 करोड़ की राशि वितरित की गई। 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों के बैंक खाते में 68 करोड़ रु. सीधे पहुंचे

पहली बार जंगल की कमाई का 20 फीसदी हिस्सा वनवासियों को दिया गया

827 वन ग्रामों को तत्काल प्रभाव से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रदेश भर की वन समितियों के सम्मेलन में शिरकत की। आयोजन जंबूरी मैदान पर हुआ। शाह ने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो पीएम ने गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों के विकास करने का उद्देश्य सबके सामने रखा था। पिछले 7-8 वर्षों से यह सब साकार हो रहा है।

21 फीसदी आदिवासियों की जिंदगी बदल जाएगी

मुख्यमंत्री चौहान की बड़ी घोषणा

तेंदूपत्ता तोड़ाई बढ़कर 300 रुपए में 100 गड्डी की गई

अब जंगल आपके सौंप दिए

भोपाल में खुलेगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी

पोस्ट-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

काबिले तारीफ... 2000 गाड़ियां, लेकिन कहीं जाम नहीं; जंबूरी मैदान सिर्फ दो घंटे में चकाचक

850 निगमकर्मियों ने 48 मैजिक, 42 डंपर लगाकर साफ किया 700 एकड़ एरिया

कार्यक्रम के बाद घर वापसी।

सफाई में जुटा निगम अमला।

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

शहर में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान ट्रैफिक और सफाई को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का समन्वय काम आया। जंबूरी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बाहर से 2000 से ज्यादा छोटे-बड़े वाहन आए थे, लेकिन कहीं बड़े ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के दो घंटे के भीतर 700 एकड़ का जंबूरी मैदान पूरी तरह साफ हो गया। नगर निगम का सफाई अमला पहले से सतर्क था। पूरे मैदान को 19 जोन में बांट कर हर एएचओ के साथ उसकी टीम लगाई गई थी। कुल मिलाकर 850 कर्मचारी, 48 मैजिक और 42 डंपर लगाकर सफाई की गई। इस दौरान लगभग 1 टन प्लास्टिक, कागज और पॉलीथिन आदमपुर छावनी भेजा गया।

अपर आयुक्त एमपी सिंह ने बताया कि पूरे मैदान को पहले तीन बड़े भागों में बांटा गया। आनंद नगर से खजूरी रोड, खजूरी रोड से करियर कॉलेज और करियर कॉलेज से स्टेज के पीछे गांधी चौक तक। हर जोन में एक-एक एएचओ की ड्यूटी लगाई गई।

इसलिए नहीं हुआ ट्रैफिक जाम

अमित शाह शुक्रवार को 8:10 घंटे भोपाल प्रवास पर थे। इस दौरान उनकी तमाम सभाओं और रोड शो के लिए ट्रैफिक व्यवस्था के भी बेहतर इंतजाम किए गए थे। इसके लिए भोपाल पुलिस ने ट्रैफिक प्लान को आठ कैटेगरी में बांटा था। ज्यादा जटिल उनका रोड शो और कार्यक्रम में आने वाले करीब 2000 वाहन थे। रोड शो के दौरान पुलिस ने उस रोड को कुछ देर आम लोगों के लिए बंद कर दिया तो बसों को शहर में घुसने ही नहीं दिया। बायपास से एंट्री और वहीं से एक्जिट देकर बसों को बगैर शहर में ट्रैफिक जाम बाहर कर दिया गया। पूरी व्यवस्था में पुलिस को दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।

रात तक 1500 से ज्यादा होर्डिंग हटाए

शहर के अलग-अलग इलाकों में रात 10 बजे तक 1500 से ज्यादा सरकारी होर्डिंग हटा लिए गए थे। इसके साथ ही चौराहों पर लगे हुए ऐसे कट आउट जो ट्रैफिक में बाधा बन रहे थे। उन्हें भी हटा दिया गया।

2.1 किमी के रोड में 80 से ज्यादा स्टेज

कश्मीरी पंडित, सिखों और बुर्का पहनीं मुस्लिम महिलाओं ने फूल बरसाए

तुलसी टॉवर से भाजपा कार्यालय तक कुल 2.1 किमी का रोड शो हुआ। इसकी शुरुआत कश्मीरी पंडितों और सिख समाज ने फूल बरसाकर की। इसके बाद नेपाली समाज ने शाह का स्वागत किया। पूरे रास्ते 80 से ज्यादा स्टेज बने थे। एक बड़े स्टेज पर करीब 300 मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने खड़ी थीं। उन्होंने शाह पर गेंदे और गुलाब के फूलों की बारिश की।

Sate cannot develop without development of 21% ST population

Shivraj govt has made tribals owner of forest, says Shah

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

827 FOREST VILLAGES CONVERTED TO REVENUE VILLAGES BY MERELY ONE CLICK BY SHAH

Appreciating welfare steps taken by chief minister Shivraj Singh Chouhan, union home minister Amit Shah said that Shivraj government had done a historical work by making tribals owners of the forest.

Shah was speaking at a function held at Jamboree Maidan here on Friday in which the income share earned from forest was distributed to forest committees (Van Samitis). Bonus to tendu leave pluckers was also distributed.

Shah was referring to the decision of Shivraj government in which 20% of the earning of the forest made through selling of forest wood and bamboo will be shared with the local van samitis. In a symbolic gesture, union home minister distributed cheque of forest share earnings to representatives of five van samitis.

"Scheduled Tribes constitute 21% of the population of Madhya Pradesh. Development of the state cannot be imagined without development of this 21% population," Shah said.

In one click, Shah announced conversion of 827 forest villages into revenue villages. "This is a historical step as these villages can now implement development schemes," said Shah.

Addressing tribals called from across the state, Shah said Shivraj Singh Chouhan had announced 17 tribal welfare schemes in Jabalpur 9 months back.

"I was extremely pleased when Shivraj ji told me about 17 schemes for tribal welfare. Some have been started and others are in final stage of implementation," said Shah.

He further said that Prime Minister Narendra Modi increased fund allocation for tribal welfare from Rs 21,000 crore during Congress rule to Rs 78,000 crore.

The Modi government has resolved to construct houses for every individual by 2022, Shah further said. Earlier, Chouhan briefed the crowd about welfare measures taken for tribal people. He announced hike in price of tendu leaves to Rs 300 per bundle from Rs 250.

Union home minister Amit Shah, CM Shivraj Singh Chouhan wave hands to crowd during road show taken out from Pranami Mandir to BJP office at Link Road no-2 on Friday. Muslims shower petals on Union Home minister Amit Shah on triple talaq during road show on Friday.

'BETTER COORDINATION NEEDED'

Union home minister Amit Shah laid emphasis on better coordination and understanding between party and government to ensure that benefits of welfare schemes reach the needy. He was addressing party's senior leaders at BJP office after road show on Friday. He said people would get benefit of welfare schemes only if explained in detail. State party president VD Sharma also expressed his views. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan and other senior leaders were present.

TONS OF RUBBISH LEFT

Tons of garbage was left at Jamboori Maidaan after Van Samiti Sammelan. Additional municipal commissioner MP Singh said 800 workers removed garbage from state hanger, Laal Parade Ground, Shymala Hills besides Jamboori Maidaan. In all, 48 dumpers, trucks and 55 collection vehicles were used to clear waste. All the areas were cleaned in 2 hours.

Road show amid heavy police presence

Kashmiri Pandits, Muslims, Nepalis, Jains shower petals on him

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

Union Home minister Amit Shah held a road show from Pranami Mandir to BJP officer on Link Road No 2 here on Friday. Heavy police force was deployed and roads were barricaded on both the sides. No one was allowed to enter the road till Amit Shah remained in BJP office.

Different communities - Kashmiri Pandits, Nepalese, Muslims, Jains - pitched tents on one side of Link Road no-2 to shower flower petals on Shah. Kashmiri Pandits welcomed Amit Shah for abolition of Article 370. Muslim women thanked him for ending instant triple talaq custom.

Amit Shah was accompanied by Chief Minister Shivraj Singh Chouhan in car in the road show. Both waved to crowds. State medical education Vishvas Sarang, BJP district president Sumit Pachori were also present.

Road show was followed by a bike rally of youths holding BJP flags. They raised slogans in favour of Shah and Chouhan. People were present in large numbers but were not allowed to join road show due to security reasons. Traffic was diverted during this period.

पोस्ट-इवेंट कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

Print Media

मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने जनजातियों को बनाया जंगल का मालिक : अमित शाह

केन्द्रीय गृहमंत्री शाह व मुख्यमंत्री ने 26 जिलों की 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में किया परिवर्तित

संवाददाता ■ भोपाल

मध्यप्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जनजाति भाइयों को सही मायने में जंगल का मालिक बनाया है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से संभव हुआ है। यह बात केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहां शुक्रवार को जंबूरी मैदान में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में कही। इसी कार्यक्रम में अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 26 जिलों के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया। शाह ने मध्यप्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में ऐसा पहली बार है, जब किसी सरकार ने जनजातियों को जंगल का मालिक बनाया है। शिवराज का यह कदम अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा, गरीबों को उनका अधिकार दिलाने की है और उस सपने को शिवराज सिंह साकार करने में जुटे हैं। कार्यक्रम में अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ रुपए का लाभांश वितरित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातियों से कहा कि ये जल, जमीन, जंगल आपके हैं। अब जंगल आप ही बचाओगे। जंगल आपको सौंप दिए गए हैं, वन विभाग सिर्फ सहयोग करेगा। (शेष पृष्ठ दस पर...)

जंबूरी मैदान से प्रदेश के जनजातियों का जीवन बदलने बड़ी सौगातें

शिवराज ने 17 घोषणाओं पर शुरू कर दिया काम

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण कार्यक्रम में शाह ने कहा कि जब वे पिछले साल जबलपुर में आए थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातियों के लिए एक के बाद एक 17 घोषणाएं कर दी थीं। तब उन्हें लगा था कि ये कैसे पूरी होंगी और आज जब वे भोपाल आए तो हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री ने जबलपुर की घोषणाओं की स्थिति पूछी। उनके जवाब से खुशी हुई कि घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में जनजाति वर्ग का केंद्रीय बजट 21,000 करोड़ का होता था जो आज मोदी सरकार में 78,000 करोड़ रुपए हो गया है। यहीं शिवराज सरकार में 925 वन ग्रामों में से 827 को राजस्व ग्राम बना दिया है, जिससे आपके अधिकार बढ़ेंगे। अंग्रेजों के समय से लेकर कांग्रेस सरकारों तक जंगल सरकारों के होते थे जिनके मालिक जनजाति भाई हो जाएंगे। 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ रुपए शिवराज सरकार ने बांटे हैं, 4800 वन समितियों को पैसा दिया है।

तेंदूपत्ता तुड़वाने के लिए अब 300 रुपए मिलेंगे

कार्यक्रम के आखिरी में मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता तुड़वाने के अभी ढाई सौ रुपए प्रति सौ गड्डी दिए जाते थे अब यह बढ़ाकर तीन सौ रुपए प्रति सौ गड्डी किए जाएंगे। जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे वे एक-एक करके जमीन पर उतार रहे हैं और गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। 89 जनजातीय विकासखंड में राशन की गाड़ी भेजने कहा था, मुझे कहते हुए खुशी है, यह राशन बंटना अधिकांश स्थानों पर प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि म.प्र ने अपने जनजाति समुदाय भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा, लाभांश आपको होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा। 9 महीने पहले अमित शाह जी जबलपुर आए थे तब हमने हमने जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने वाले 14 फैसले किए थे। (शेष पृष्ठ दस पर...)

कार्यालय में ली प्रदेश पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश मंत्रिमंडल के साथ बैठक

भोपाल में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत

विशेष संवाददाता ■ भोपाल

शुक्रवार को एक दिवसीय भोपाल प्रवास पर आए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल में भव्य स्वागत हुआ। कृष्ण प्रणामी मंदिर से प्रदेश भाजपा कार्यालय के बीच हुए स्वागत के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे श्री शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की उपस्थिति में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों एवं राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की।

शुक्रवार को भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह और जम्बूरी मैदान पर वन समितियों के सदस्यों को कुल राजस्व में से लाभांश का 20 प्रतिशत राशि और तेंदू पत्ता संग्राहकों को लगभग 70 करोड़ रुपए के बोनस के वितरण कार्यक्रमों के बाद लाल परेड मैदान से सड़क मार्ग से प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बीआईपी रोड नं. 2, 5 नंबर चौराहा पर स्थित श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर से भाजपा कार्यालय तक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री शाह का भव्य स्वागत किया। स्वागत मार्ग में हर 20 कदम की दूरी पर बनाए गए मंचों से कार्यकर्ताओं ने श्री शाह के मार्ग एवं वाहन पर पुष्पवर्षा की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी व भारत माता की जय, वंदे मातरम और जयश्री राम के नारे लगाए। स्वागत के लिए भाजपा ने विभिन्न मोर्चों, संगठनों और स्थानीय नेताओं को अलग-अलग स्थानों पर जिम्मेदारी दी गई थी।

पोस्ट-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

भोपाल के जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

पहली बार कोई सरकार जंगल में रहने वालों को बना रही है जंगल का मालिक

तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति सौ गड्डी पर मिलेंगे अब 300 रुपए : सीएम

भोपाल ■ प्रशासनिक संवाददाता

देश की सबसे अधिक जनजाति आबादी वाले राज्य मप्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने इसके संकेत भी दिए। उन्होंने पिछले जबलपुर दौरे का जिक्र कर वहां किए गए वादों को पूरा करने के बाद आशीर्वाद के लिए आने की बात कही। उन्होंने कहा कि जबलपुर में तय किए 17 बिंदुओं को पूरा करने के बाद ही आपके पास आशीर्वाद के लिए आएंगे। उन्होंने जनजाति वर्ग की उपेक्षा के लिए पिछली सरकार को भी घेरा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को राजधानी के जंबूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित किया। (शेष पेज 4 पर)

राजधानी भोपाल स्थित जंबूरी मैदान में तेंदूपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को जनजातीय संस्कृति के प्रतीक तीर-कमान भेंट किए गए।

जनजातियों को अब मिलेगा यह फायदा

- अब मप्र में कीमती सागवान लकड़ी के साथ ही अन्य वन संपदा की 20 फीसदी राशि के मालिक वनवासी होंगे।
- बांस और अन्य उत्पादन के लिए राशि वितरण के साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों को करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान। ■ मप्र के 925 में से 827 वन ग्राम को राजस्व ग्रामों की तरह सुविधाएं देने की शुरुआत। अब यहां परिसीमन हो सकेगा। आवास के लिए ऋण मिल सकेगा और राजस्व के सभी अधिकार वनवासियों को प्राप्त होंगे। ■ प्रदेश में 15 हजार 600 से अधिक ग्राम सभाओं में वन समितियों के माध्यम से ग्रामीणता से कार्य किए जा सकेंगे।

कार्यक्रम में यह रहे मौजूद

इस सम्मेलन में श्री शाह और श्री चौहान के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय खाद्य, उद्योग एवं जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल, इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डा. एल मुरुगन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, विजय शाह, अरविंद भदौरिया के साथ भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह भी मौजूद रहीं।

झलकियां

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठीक 2.35 बजे जंबूरी में मंच पर पहुंचे।
- शाह का स्वागत केंद्र और राज्य के मंत्रियों ने कतारबद्ध होकर किया।
- अमित शाह के भाषण के बाद सीएम चौहान माइक के पास पहुंचे और कहा कि वे एक बात बोलना भूल गए थे। उन्होंने इस दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति 100 गड्डी पर मिलने वाले पारिश्रमिक को 250 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा की।
- जब सीएम भाषण देने आए तो उनके माइक पर पहुंचने से पहले ही सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाने का प्रयास किया, लेकिन बाजू में बैठे गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उनका कुर्ता पकड़कर उन्हें वापस बिठा दिया।
- सम्मेलन स्थल पर शाह के स्वागत के बाद सागर से आए कलाकारों ने बधाई नृत्य पेश किया।
- जब स्वागत में पौधों के गमले भेंट करने की बारी आई तो थोड़ी देर इंतजार करने की नौबत आ गई। कलेक्टर भोपाल भागते हुए गए और फिर गमलों के आने का सिलसिला शुरू हुआ।

गृह मंत्री ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर नमन किया।

शाह के शो की झलकियां

मुस्लिम महिलाओं ने गृहमंत्री का काफिला गुजरने पर फूल बरसाए।

पोस्ट-इवेंट कवरेज

Print Media

जंगल अब आदिवासियों के... जंबूरी मैदान से शाह की घोषणा के साथ ही सरकार ने जारी किया आदेश

आदेश के मायने
जंगल से होने वाली आय का 20% हिस्सा आदिवासियों को मिलेगा

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9425018933

शाह ने पूछा - 8 माह पहले की गई पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ, सीएम बोले - सभी पर काम चल रहा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वनवासी हितैषी घोषणा करते हुए 21% अनुसूचित जनजाति आबादी को साधा। जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन में शाह ने 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने जंगल से होने वाली कमाई में 20 फीसदी हिस्सेदारी वनवासियों को दिए जाने की भी घोषणा की।

शाह ने मंच से सीएम की तारीफ करते हुए कहा- देश में पहली बार कोई सरकार जनजातीय भाइयों को जंगलों का मालिक बनाने का काम कर रही है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच से तेंदूपत्ता संग्राहकों को 250 रुपए प्रति सौ गड्डी की जगह 300 रु. देने की घोषणा की। उन्होंने वनवासियों से कहा कि वन ग्राम बनाने का आदेश आज ही जारी कर दिया गया है। ये जमीन और जंगल आपके हैं। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी, उसकी आय आप ही प्राप्त करेंगे। वन विभाग केवल सहयोग करेगा।

भाजपा मुख्यालय के बाहर रोड शो के दौरान शाह का जबरदस्त स्वागत किया गया।

अमित शाह 8 माह पहले जबलपुर आए थे। शुक्रवार को जंबूरी मैदान आते वक्त कार में उन्होंने सीएम से वहां की गई 17 घोषणाओं का हिसाब पूछा। सीएम ने उन्हें बताया कि सभी घोषणाओं को धीरे-धीरे जमीन पर उतार रहे हैं। अगले साल तक सभी पूरी हो जाएगी।

2023 से पहले आदिवासियों पर फोकस, क्योंकि...

मप्र में 6 महीने के भीतर ही आदिवासियों को केंद्रित कर भाजपा ने दूसरा मेगा कार्यक्रम कर अगले चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकता बता दी है। इसके पीछे 2018 के चुनाव में हाथ से सत्ता फिसल जाने की कसक भी है। तब भाजपा 7 सीटों से चूक गई थी, जबकि उसे कांग्रेस से एक फीसदी ज्यादा वोट मिले थे। पार्टी का मानना है कि आदिवासी क्षेत्रों में ही उसे करीब डेढ़ से दो दर्जन सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 2013 में भाजपा के खाते में 31 सीटें आई थीं लेकिन 2018 में मात्र 16 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। मिशन 2023 के लिए भाजपा इसी की भरपाई करने में जुटी है।

पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और भाजपा दफ्तर में सत्ता संगठन को दिए मंत्र

अब अंग्रेजों के जमाने की डंडाबेस नहीं, डाटा बेस पुलिसिंग का जमाना

सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करने पहुंचे शाह ने कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली पुलिस का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी वाली पुलिस का दौर है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को नए सिरे से रणनीति बनाकर लगातार रिव्यू करना होगा। अब डंडाबेस नहीं, बल्कि डाटाबेस का जमाना है। शाह ने सीपीटीए में पुलिस विज्ञान पर आधारित 5 किताबों का विमोचन भी किया।

- कानून व्यवस्था पर पॉलिटिक्स में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
- अपराधी से 2 कदम आगे हो पुलिस की तकनीक।
- राज्य सूचनाओं का आदान प्रदान सतर्कता से करें।
- कश्मीर-नॉर्थ ईस्ट से उग्रवाद और आतंकी ग्रुप खत्म हुए।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने समस्याओं पर सफलता हासिल की है। चाहे वह कश्मीर समस्या हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद की समस्या हो, चाहे नार्थ-ईस्ट के अंदर हथियारबंद समूहों की बात हो। ढेर सारे हथियारबंद ग्रुपों ने हथियार डाले और मुख्यधारा के अंदर आए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल कमांडिंग वर्चस्व की स्थिति में हैं। वामपंथी उग्रवाद भी समाप्त होने की दिशा में है। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो वामपंथी आतंकवादी लगभग-लगभग बाहर ही निकल गए।

मंत्री-नेताओं को दिया स्मार्ट वर्किंग का मंत्र, बोले- मजदूरी नहीं, परिश्रम करें

शाह ने सत्ता-संगठन को स्मार्ट वर्किंग का मंत्र दिया। उन्होंने चुनाव के लिए कमर कसने की समझाइश दी। कहा मिशन 2023 के लिए हम्माली या मजदूरी नहीं, परिश्रम पर फोकस करें। उन्होंने मप्र भाजपा के कार्यक्रमों की तारीफ की। उन्होंने मंत्रियों और पार्टी कोर ग्रुप के साथ चर्चा की और उन्हें सफलता के मंत्र दिए।

- योजनाबद्ध परिश्रम करने से मिलते हैं बेहतर रिजल्ट।
- समस्या देखने का नजरिया बदलने पड़ेगा जरूरी है।
- संगठन सत्ता का बैक बोन, उसके बिना जीत असंभव।
- मप्र भाजपा के बूथ विस्तार सहित अन्य कार्यक्रम अच्छे।

भार्गव अच्छे नेता, लेकिन...

जातिवादी राजनीति से ऊपर उठने की बात करते हुए शाह ने कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री गोपाल भार्गव अच्छे जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन इन्हें ट्राइबल क्षेत्र में भेजेंगे तो अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे।

नहीं उड़ सका हेलिकॉप्टर

भाजपा मुख्यालय की बैठक के बाद शाह की मुख्यमंत्री चौहान और प्रदेश अध्यक्ष शर्मा के साथ कमरा बंद चर्चा कुछ लंबी खिंच गई। फलस्वरूप शाह को सड़क मार्ग से स्टेट हैंगर जाना पड़ा, क्योंकि अंधेरे के कारण हेलिकॉप्टर उड़ नहीं सका।

पेज 9 भी पढ़ें

जंबूरी मैदान पर वन समितियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

शाह ने अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया।

पोस्ट-इवेंट कवरेज

Print Media

भोपाल के जंबूरी मैदान पर वन समितियों के सदस्यों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज ने की घोषणा

तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब 250 रुपए प्रति सौ गड्डी के स्थान पर मिलेंगे 300 रूपए

स्टार समाचार | भोपाल

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन में शुक्रवार को किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे। चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। 22 लाख हितग्राहियों के खाते में 125 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। यह वनवासी भाई-बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मप्र में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 250 रुपए प्रति सौ गड्डी के स्थान पर अब 300 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शक्तिशाली और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए कार्य किया है।

छेड़ेंगे नहीं, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं

इससे पहले शिवराज ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने पर कितनी बातें कही जाती थी। यह हट गई तो आग लग जाएगी। एक झटके में धारा 370 खत्म करने वाले हमारे नेता आए हैं। अरे खून तो दूर पत्ता भी नहीं हिला। अमित शाह का साफ कहना है कि हम अपनी तरफ से छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई देश की तरफ अंगुली उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी दिशाओं में विकास कर रहा है। कार्यक्रम में मप्र के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल. मुरुगन, केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत राज्य सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से वनों में रहने वाले एक लाख से ज्यादा लोग पहुंचे।

जनजाति वर्ग को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है, इसका लाभ जनजाति वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग के लोगों को शिक्षण शुल्क सुविधा, उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और रोजगार के साधनों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया पर नियंत्रण के लिए भी कार्य हो रहा है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी इस कार्य में मार्गदर्शन दे रहे हैं।

पेसा एक्ट बदलने की प्रक्रिया शुरू

शिवराज ने कहा कि हमने तय किया था पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आदिवासी भाई-बहनों की जिंदगी बदलने के लिए पेसा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गई है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया है। आपने प्रदेश में घने जंगल बढ़ाने का काम किया है। यह जल, जमीन, जंगल आपके हैं। अंग्रेजों ने ऐसे काले कानून बना दिए थे कि घुस नहीं सकते। पत्ता नहीं तोड़ सकते। जिंदगी दूभर कर दी थी। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जंगल आप ही बचाएंगे। इसे बदलने की प्रक्रिया भी ग्रामसभा तय करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी भाइयों को जंगल सौंपने का तय किया है। वन विभाग सिर्फ सहयोग करेगा।

आदिवासियों के लिए केंद्र-राज्य सरकारों के काम गिनाए

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी सवा एक साल बचा है लेकिन भाजपा का चुनावी बिगुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजा दिया है। वहीं आदिवासियों को भी साध गए। उन्होंने आदिवासियों के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के कामों को भोपाल के जंबूरी मैदान पर शाह ने गिनाया। वहीं, अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए कांग्रेस के 70 साल के शासन में कोई प्रयास नहीं किए जाने के आरोप भी लगाए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम के अधिकार देने की शुरुआत की। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में वन समितियों के लाभांश में वृद्धि के साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभांश का वितरण किया। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश ने 10 वर्षों में जीडीपी में 200 प्रतिशत की वृद्धि की है। मोदी सरकार आदिवासी समुदाय के ऊपर 78 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि जो 17 निर्णय मप्र सरकार ने आदिवासियों के लिए लिए थे उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान ने निरंतर कार्य किया है। मध्यप्रदेश अब विकसित राज्यों में शामिल है।

पोस्ट-इवेंट कवरेज

Print Media

भोपाल के विभिन्न वार्डों के कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने लिंक रोड नंबर एक पर पांच नंबर पेट्रोल पंप के पास गृह मंत्री का स्वागत किया।

जंबूरी मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री को तीर कमान और जैकेट भेंट किए गए।

मिशन 2023 : अमित शाह ने दिया स्मार्ट वर्किंग का मंत्र, बोले- संगठन ही सर्वोपरि है

बड़े नेता लें हारने वाले बूथों को जिताने की जिम्मेदारी

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425144091

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सत्ता-संगठन को स्मार्ट वर्किंग का मंत्र देते हुए अगले चुनाव के लिए कमर कसकर जीत का परचम फहराने की समझाइश दी है। उन्होंने कहा मजदूरी नहीं, परिश्रम पर फोकस करें। कामकाज में सुधार की नसीहत और सफलता के टिप्स भी दिए। शाह बोले-जातिवाद से बाहर निकलो, सरकार के अच्छे कामों को संगठन ठीक से नीचे तक लेकर जाए। बड़े नेता कमजोर बूथों को जिताने की जवाबदारी लें। उन्होंने संगठन पर्व के कार्यक्रमों और बूथ विस्तार योजना की तारीफ करते हुए सुधार की गुंजाइश भी बताई। यहां उन्होंने दिग्गज नेताओं से दो टूक कहा कि संगठन ही सर्वोपरि है। सरकार कितना भी अच्छा काम करे लेकिन चुनाव संगठन के दम पर ही जीते जाते हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से कई मुद्दों पर चर्चा की। यह भी कहा कि कांग्रेस वैचारिक पार्टी नहीं रही। भाजपा ही देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है। उन्होंने संगठन के बूथ विस्तार, डिजिटलाइजेशन और संगठन पर्व के कार्यक्रमों की सराहना की।

यह भी बोले शाह

- शिवराजजी अच्छा काम कर रहे लेकिन संगठन भी सरकार की योजनाओं को ठीक से नीचे तक लेकर जाए।
- ठाकरेजी संगठन को जहां तक लेकर आए, हम उसे और आगे लेकर जाएं।

1 सियासी सफलता के राज

अमित शाह ने अपनी सियासी यात्रा के मौजूदा मुकाम तक पहुंचने के टिप्स भी साझा किए। अपने अनुभव और संस्मरण बताते हुए कहा कि मजदूरी के बजाए योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करने से ही रिजल्ट मिलते है। उन्होंने अपने पढ़ने के शौक की जानकारी भी दी। उल्लेखनीय है कि शाह के गांव में परिवार की बड़ी लाइब्रेरी भी है। शाह के करीबी बताते हैं कि यही वजह है कि किसी भी समस्या को उनके देखने का नजरिया अलग रहता है। इसी नजरिए में ही समस्या का हल मिलता है।

2 मुरली-सीएम से चर्चा

दोपहर में मुख्यमंत्री आवास में भोजन के बाद शाह ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ कुछ देर अकेले में चर्चा की। उन्होंने किस विषय पर बात की यह खुलासा नहीं हो सका। शाम को शाह ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे और पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वह पार्टी पदाधिकारियों, मंत्रियों और कोर ग्रुप की बैठक में व्यस्त हो गए।

3 बैठक में ये रहे मौजूद

शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, एल मुरुगन, निशीथ प्रामाणिक, पार्टी की प्रदेश सह प्रभारी पंकजा गोपीनाथ मुंडे मौजूद थी। इनके अलावा प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, ओपी सकलेचा, भूपेंद्र सिंह सहित शिवराज कैबिनेट के सभी सदस्य और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

शाही स्वागत

भोपाल। भाजपा के ताकतवर दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में पहली बार सत्ता-संगठन ने पलक-पांवड़े बिछा दिए। लिंक रोड पर दो किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान सड़कों पर फूलों की चादर बिछ गई। श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर से 7 नंबर चौराहे तक 130 से अधिक स्वागत मंच बनाए गए थे।

मुस्लिम महिलाएं और यूक्रेन के छात्र

जिन रास्तों से उनका काफिला निकला वहां चारों तरफ बड़े-बड़े कटआउट्स और होर्डिंग-पोस्टर्स ही नजर आ रहे थे। भोपाल उत्तर क्षेत्र से प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं स्वागत के लिए पहुंची थी। वे सभी अपने हाथ में तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए शाह का आभार जता रही थीं। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों ने भी स्वागत मंच लगाकर उनका स्वागत किया।

खातों में डाले 125 करोड़

जंबूरी मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 22 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में लाभांश के 125 करोड़ रुपए डाले गए। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि वनवासियों को 20 प्रतिशत लाभांश देने वाली यह पहली सरकार है। प्रदेश में करीब एक हजार करोड़ रु. सालाना सरकार को वनों से आय मिलती थी। अब उसका हिस्सा वनवासियों को मिलेगा।

शाह के शो की झलकियां

मुस्लिम महिलाओं ने गृहमंत्री का काफिला गुजरने पर फूल बरसाए।

पोस्ट-इवेंट कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

Print Media

पत्रिका, भोपाल
23 APR 2022

भोपाल में 9 घंटे रहे गृह मंत्री अमित शाह: वन समितियों के सम्मेलन में शिरकत की, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का किया शुभारंभ

शाही शो... 'केन्द्र' में कश्मीरी पंडित, महिलाएं व आदिवासी

शाह व शिव के ऐलान

1. भोपाल में भी बनेगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी
2. तेंदूपत्ता तुड़वाई की मजदूरी ₹250 से बढ़ाकर ₹300 की

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का शुक्रवार को भोपाल दौरा मेगा-शो की तरह रहा। वे शहर में करीब 9 घंटे रहे। इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरा दौरा कश्मीरी पंडित यानी हिंदू, तीन तलाक यानी महिलाएं व आदिवासी वर्ग पर केंद्रित रहा। शाह ने पहले पुलिस के कार्यक्रम में शिरकत की, फिर वन समितियों के सम्मेलन में जम्बूरी मैदान पहुंचे। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा रोड शो किया। अंत में भाजपा दफ्तर में नेताओं के साथ बैठक की।

सबसे पहले शाह ने सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में दो दिनी 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। यहां उन्होंने कहा, अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली नहीं, बल्कि नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी होगी, तर्क वाली पुलिसिंग करनी होगी। उन्होंने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया।

शाह ने जम्बूरी मैदान में राज्य सरकार के वनवासी समितियों को जंगल की कमाई में 20% हिस्सेदारी देने पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के समय में जंगल की कमाई सरकार के हाथ में रहती थी, लेकिन देश में ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार ने जंगल की कमाई में वनवासी समितियों को 20% हिस्सेदारी दी है। उन्होंने कहा, आज 925 में से 827 वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया है। ये आपके जीवन में बड़ा फैसला है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब तेंदूपत्ता तुड़वाई की दर 300 रुपए कर दी गई। इससे पहले 100 बंडल पर 250 रुपए मिलते थे। संबंधित@राजनीति पेज

गृह मंत्री ने की शिवराज की तारीफ

शाह ने शिवराज की तारीफ करते हुए कहा, मप्र को छोड़कर देश में शायद ही किसी राज्य ने 10 साल में सकल घरेलू उत्पाद में 200 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की हो। बोले- पिछली बार जब जबलपुर आया था तब शिवराज ने 17 घोषणाएं की थीं। मैंने कहा था कि घोषणा तो कर दी, पर जनता हिसाब मांगती है। इस बार पता चला कि सभी घोषणाएं पूरी हो गईं। आज की घोषणाओं को 2024 से पहले पूरा करेंगे। शिवराज ने कश्मीर से धारा-370 हटाने पर शाह की तारीफ की।

सीएम बोले- ये जिंदगी बदलने का अभियान...

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने वो काम किए, जो पहले सोच नहीं सकते थे। धारा-370 हटाने पर कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी लेकिन संसद में एक झटके में धारा-370 समाप्त कर दी। आज कश्मीर में शांति है। शिवराज ने कहा कि यह सम्मेलन वनवासियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। अब वनग्राम राजस्व ग्राम बन जाएंगे। इससे वनवासी के खाते बनेंगे, जमीन का नामांतरण होगा, कर्ज व मुआवजा मिल सकेगा, फसल मुआवजा मिलेगा, पंजीयन उपार्जन होगा और उसे उसका हक मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने कभी ये नहीं किया।

प्रदेश के खजाने को इवेंट के नाम पर लुटाया: नाथ

केंद्रीय गृह मंत्री को बुलाकर भाजपा ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस बांटने के नाम पर आयोजन किया। 67 करोड़ रुपए का बोनस बांटने के लिए 20-25 करोड़ रुपए इस इवेंट के नाम पर लुटा दिए। भाजपा प्रदेश के खजाने को इवेंट के नाम पर लुटाती है। - कमलनाथ, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस

सम्मेलन में शाह को तीर-कमान भेंट किए गए। साथ में सीएम शिवराज सिंह।

मध्यप्रदेश की भूमि पर आना हमेशा विशेष अनुभव होता है। आज राजा भोज की नगरी भोपाल में जनता के इस अपार स्नेह एवं आशीर्वाद के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। -अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

एक तीर से साधे तीन निशाने

1. **आदिवासी:** वनवासी सम्मेलन के जरिए प्रदेश में 21% आबादी वाले आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। भाजपा के प्रदेशिक और राष्ट्रीय एजेंडे में अब दलित-आदिवासी प्राथमिकता में हैं। प्रदेश में 41 आदिवासी सीटें हैं। इनमें 16 सीटें 2018 के चुनाव में भाजपा जीती थी। 2003 में 41 में से 37 सीट भाजपा को मिली थीं।
2. **हिन्दू वोट बैंक:** शाह के रोड-शो में कश्मीरी पंडितों ने स्वागत किया। इस कदम से हिन्दू वोट बैंक को साधा गया, क्योंकि 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म के बाद से कश्मीरी पंडित सुर्खियों में हैं। एक बड़े वर्ग की सहानुभूति कश्मीरी पंडितों के साथ है।
3. **मुस्लिम वोट:** भाजपा ने ध्यान रखा कि मुस्लिम विरोधी छवि न जाए, इसलिए कश्मीरी पंडितों के बाद मुस्लिम महिलाओं ने शाह का स्वागत किया। तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन प्रदर्शित करते हुए यह स्वागत किया गया।

TIMES OF INDIA, BHOPAL
23 APR 2022

Shah's Second Visit To MP In 7 Months; Focus On Tribals

Two-hour closed-door meet with CM & state leaders

Times News Network

Bhopal: Union home minister Amit Shah received a grand reception from BJP workers in Bhopal on Friday evening. Thousands of party workers thronged both sides of the road, waving flags and holding placards on the 4km from Lal Parade grounds to the BJP office.

The convoy reached Deendayal Parisar, the state BJP headquarters, around 8pm. Priests chanted mantras as Shah entered the office for a meeting with party leaders.

A large police contingent was posted around the building to keep media, party workers and crowds at a distance. The entire area was heavily barricaded. Those who were permitted inside included CM Shivraj Singh Chouhan, state party president VD Sharma, Union ministers Prahlad Patel, Jyotiraditya Scindia, state cabinet ministers Gopal Bhargava and Narottam Mishra, party national general secretary Kailash Vijayvargiya, national general secretary in-charge Muralidhar Rao, Jabalpur MP Rakesh Singh and former Union minister Pankaja Munde.

Home minister Amit Shah at the forest committee meet on Friday

With assembly elections only 17 months away, Shah spent two hours discussing organisational matters with party leaders.

In the last seven months, there have been two visits of Amit Shah and one by Prime Minister Narendra Modi to the state — each time to address a tribal congregation.

It is clear that BJP's target is tribal voters for 2023 assembly elections. Tribals comprise of 2crore population in MP and influence 86 of the 230 seats. Forty seven constituencies are tribal reserved. In 2013, BJP won 31 tribal reserved seats but in 2018, tribal voters swung to Congress and BJP got only 16 seats. Having learnt its lesson, BJP is trying to woo tribal voters back.

Former CM Kamal Nath took a dig at the home minister's visit to the state. "Amit Shah is welcome to Madhya Pradesh. He needs to come and see the bad conditions that prevails here. The 'kalakari' that is happening here and how people are being betrayed. Every section of society is distraught and only announcements are made by the government. They are acting and think people do not understand. People are very sensible these days, they understand everything," he said.

Shivraj has transformed MP, says home minister

Times News Network

Bhopal: Union home minister Amit Shah praised Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan saying that he has made a special contribution in transforming the state into a developing one from a BIMARU state.

Before the commencing the 48th All India Police Science Congress meet organised at Central Police Training Academy (CAPT) in Bhopal, Shah and Chouhan paid floral tributes and garlanded martyrs at Shaheed Memorial in the premises. Plantation was also done at all religious places in the campus, and exhibition of new equipment was inaugurated on the occasion of All India Police Science Congress in the academy.

The CM said that it is the duty of police to protect good citizens and suppress the wicked according to the verse of Gita "Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Dushkritam". "In Covid-19, the police presented exemplary examples of service. The police have to tackle challenges like de addiction campaigns, safety of daughters and control of cyber crime. Therefore, training of the police, facilities for scientific investigation, availability of tools of investigation and every possible use of forensic science is the need of the hour," he said. The MP police force has grown from 83,568 personnel in 2011 to 1,26,000 today, Chouhan said, adding that new recruitments are in the offing.

CM Shivraj Singh Chouhan welcomes home minister Amit Shah

More than 21,000 acres of land, worth over Rs 12,000 crore, has been freed in the crackdown on land mafia, the CM said.

Chouhan also said Dial 100 is providing rapid police assistance to people. Urja Mahila Desk and Crime & Criminal Tracking Network & System are running smoothly. The system of citizen services has been improved through the MPeCop app.

पोस्ट-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

दैनिक जागरण, भोपाल
23 APR 2022

देश में पहली बार मप्र में आदिवासी जंगल के मालिक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित किया

26 जिलों के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का हुआ शुभारंभ

अमित शाह ने मंच से मुख्यमंत्री शिवराज की जमकर तारीफ की

शाह ने साढ़े 13 मिनट के भाषण में 13 बार सीएम शिवराज का नाम लिया

मुख्य प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। अंग्रेजों के समय से जंगलों की मालिकी सरकारों के पास रहती थी। अब मप्र में कीमती सागवान लकड़ी के साथ ही अन्य वन संपदा की 20 प्रतिशत राशि के मालिक वनवासी होंगे। मप्र ने यह युग परिवर्तनकारी कार्य किया है। मप्र सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाला राज्य है। सीएम शिवराज ने मप्र के 21 प्रतिशत आदिवासियों के कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं, वे पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। आज का दिन सिर्फ मप्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय मंत्री शाह शुक्रवार को राजधानी के जंबूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित कर ▪ शेष पृष्ठ 9 पर

- कहा- शिवराज ने मप्र को बीमारू से विकसित राज्य बनाया
- मोदी के स्वप्न को साकार करने का काम कर रहे हैं शिवराज
- मप्र में शिवराज के नेतृत्व और मोदीजी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है
- मुख्यमंत्री बोले- तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब 250 रुपए प्रति सौ गड्डी के स्थान पर मिलेंगे 300 रुपए

वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से वनवासियों की संवर जाएगी जिंदगी

कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जल, जमीन और जंगल वनवासियों के हैं। वनों से अर्जित आय का हिस्सा प्राप्त कर वनवासी वनों के विकास में सहयोग करेंगे। वन विभाग सहयोगी की भूमिका में होगा। वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बन जाने से बंटवारा और नामांतरण होने के साथ फसलों की गिरदावरी भी हो सकेगी। प्राकृतिक आपदा पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, आंगनवाड़ी और विद्यालय भवन स्वीकृत होंगे। ग्राम सभा के माध्यम से वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य का अवसर मिलेगा। वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से वनवासियों की जिंदगी संवर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 22 लाख हितग्राहियों के खाते में 125 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों ▪ शेष पृष्ठ 9 पर

शाह ने ऐसे की शिवराज की तारीफ

- वर्ष 2021-22 में मप्र द्वारा 19.7 प्रतिशत विकास दर हासिल करना बड़ी बात है।
- मप्र में गत 10 वर्ष में 200 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, जो अन्य राज्यों में नहीं हुई।
- प्रदेश में पूंजीगत व्यय 31 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 40 हजार करोड़ तक हो गया है।
- मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में खाद्यान्न वितरण के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार की महिलाओं को 1000 रुपए का आहार अनुदान भी दिया जा रहा है।

827 वन ग्राम बनाए जाएंगे राजस्व ग्राम

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने रिमोट से बटन दबाकर वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने के कार्य की शुरूआत की। इस कार्य के लिए प्रदेश के 26 जिलों के 827 ग्राम चयनित किए गए हैं।

देश में कॉमन सिविल कोड जल्द लागू होगा

भोपाल। देश में कॉमन सिविल कोड को केन्द्र सरकार जल्द लागू करने की तैयारी में है। यह जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में दी। शाह ने बताया कि हम कॉमन सिविल कोड पर विचार कर रहे हैं और इसे जल्द लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा के अगले सत्र में इसे केन्द्र सरकार संसद में पेश करेगी। धारा 370 खत्म करने के बाद से ही माना जा रहा था कि अब केन्द्र सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। शाह ने भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में इसके साफ संकेत भी दे दिए।

जनता के अपार स्नेह के लिए हृदय से आभार

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट की गई। इसमें कहा गया कि मप्र की भूमि पर आना हमेशा एक विशेष अनुभव होता है। आज राजा भोज की नगरी भोपाल में जनता के इस अपार स्नेह एवं आशीर्वाद के लिए, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

MP first state turned tribals into forest dwellers

STAFF REPORTER ■ BHOPAL

This is the first time in the country that a state has turned tribals into forest land owners," Home Minister Amit Shah said on Friday, praising Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan.

Shah was here for a tribals' convention and also took part in a mega road show, which culminated at the Bharatiya Janata Party (BJP) head quarters, where the minister addressed the party cadre.

Addressing the tribal population at Jamboorie ground, Shah said: "Offering forest land ownership rights to the tribal community is an exemplary step by Chouhan. Prime Minister Narendra Modi has envisioned that poorest of the poor should be empowered and Chouhan is realising this dream."

Announcing a bonus for tendu patta collecting tribals and conversion of 827 Van Grams into revenue villages, he said, "This will make you feel that you also deserve ownership in the state," he said.

The state government has given Forest Village Committees 20% share in forest income. The state has 21% tribal population. Shah said the state can't progress unless the tribals are on the path of development. "Our announcements for tribals won't stop and will be completed," he said.

Union Home Minister Amit Shah being presented a traditional bow and arrow as Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan looks on during forest committees convention at Jamboree ground , in Bhopal on Friday. Pioneer photo

Addressing the crowd, Chouhan said a bonus distribution of Rs 125 crore for 22 lakh tribal beneficiaries has begun. "For the first time, forest dwellers will be entitled to compensation in case of natural calamities. Once the conversion of Van Grams into revenue villages takes place, the land records will be maintained, and mutation and division of land will take place. The process will be governed by Gram Sabhas, while the Forest department will only offer assistance," said Chouhan.

Shah's visit to Bhopal is part of the BJP's efforts to woo tribals ahead of the 2023 assembly polls and 2024 Lok Sabha elections. The party had organised a 2-km roadshow for Shah. The roads were decked up and flower petals were showered on the minister. Shah held a meeting with the core committee at the headquarters.

Police need knowledge, evidence and logic, said the Union Home Minister while addressing the 48th All India Police Science Congress in Bhopal. He announced that the city will get a National Forensic Science University. Police need technology to be two steps ahead of the criminals, said Shah, adding even constable and head constable-level staffers are required to be tech-savvy.

पोस्ट-इवेंट कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

Print Media

2 3 APR 2022

THE INDIAN EXPRESS
DELHI EDITION Page No..

MP: Shah gives cheques to tendu leaf collectors

IRAM SIDDIQUE
BHOPAL, APRIL 22

Union Home Minister Amit Shah

IN HIS second visit to Madhya Pradesh in seven months, Union Home Minister Amit Shah arrived in Bhopal on Friday morning to continue the party's tribal outreach ahead of next year's Assembly elections.

Shah on Friday set in motion the processof distributing Rs 125 cores worth cheques among 22.6-lakh tendu patta collectors for the year 2020-21 after inaugurating the Forest Produce Collectors' Convention in the city's Jamburi Maidan.

The tendu patta is the biggest source of livelihood for tribals in the state.

In his address at the convention, Shah said 827 forest villages in 26 districts have been transformed to revenue villages. Spelling out the details, he further said that 827 out of 925 forest villages will start getting facilities like revenue villages. Delimitation will be possible here, loans for housing will be available and all the rights of revenue will be provided to the forest dwellers, he said. "The representatives of the forest dwellers who came to the conference will go back today with a sense of self-respect. Works can be done on priority through forest committees in more than 15,600 gram sabhas in the state," Shah said. Madhya Pradesh has the highest tribal population of 21% in the country. "Chief Minister Chouhan made Madhya Pradesh a developed state from a bimaru state," Shah added.

Chouhan said that a campaign is underway to "change the lives of vanvasi brothers and sisters". He also announced that in Madhya Pradesh, instead of Rs 250 per hundred bundles, Rs 300 will be given to the tendu patta collectors.

2 3 APR 2022

THE HINDUSTAN TIMES
DELHI EDITION Pag

FUNDS FOR TRIBAL WELFARE HAVE INCREASED UNDER MODI GOVT: SHAH

Shruti Tomar
letters@hindustantimes.com

BHOPAL: Prime Minister Narendra Modi is committed to the welfare of tribals and has allocated ₹78,000 crore for various schemes and programmes for the community ever since he assumed office in 2014, Union home minister Amit Shah said on Friday.

"This is a government of the poor, Scheduled Tribes, Dalits and Backward Classes. During the Congress government's time, only ₹21,000 crore was provided for the welfare of (tribal) people, but after Prime Minister Modi came to power in 2014, funds for tribal uplift were enhanced to ₹78,000 crore," Shah said.

The Union minister was speaking at 'Van Samiti Sammelan', a programme where bonus was distributed to collectors of forest produce such as tendu leaves and forest societies when he made the statement.

Tribals constitute more than 21% of the state's population. This was the second tribal outreach by Shah in just over six months in the BJP-ruled state where assembly elections are due in 2023.

State Congress chief Kamal Nath hit back, saying: "Crores of rupees have been spent today in the name of this event. The Congress worked genuinely for the welfare of tribals and the poor but the BJP is focusing more on taking the credit..."

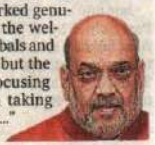

2 3 APR 2022
FIRST INDIA
DELHI EDITION
Page No...

Shah: Tribal welfare funds increase to ₹78,000 crore

Bhopal (PTI): Prime Minister Narendra Modi increased the allocation of funds for the welfare of tribal communities drastically after coming to power in the Centre, Union Home Minister Amit Shah said on Friday.

He was speaking at 'Van Samiti Sammelan', a program where bonus was distributed to collectors of forest produce such as Tendu leaves. "This is a government of the poor, Scheduled Tribes, dalits and backward classes. During Congress government's time, only Rs 21,000 crore were provided for the welfare of (tribal communities) people, but after Modi came to power in 2014, it has been enhanced to Rs 78,000 crore," Shah said.

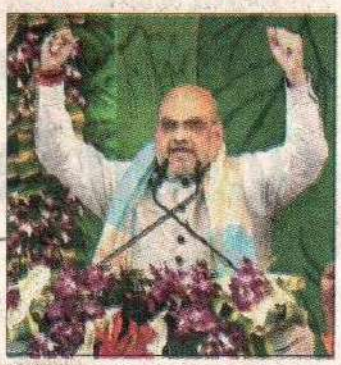

Home Minister Amit Shah addresses the 'Van Samiti Sammelan' in Bhopal.

2 3 APR 2022

MILLENIUM POST
DELHI EDITION

Page No. 06

Shah: Under Modi govt, funds for tribal welfare have increased to ₹78K crore

OUR CORRESPONDENT

BHOPAL: Reaching out to tribals who constitute more than 21 per cent of Madhya Pradesh population, Union Home Minister Amit Shah on Friday said the Narendra Modi government was committed to their welfare and pointed out it had allocated Rs 78,000 crore for various schemes and programmes targeted at the community after assuming office in 2014.

He also said the Modi government has resolved to construct houses for each and every individual by 2022- end.

This is a government of the poor, Scheduled Tribes, Dalits and Backward Classes. During the Congress government's time, only Rs 21,000 crore was provided for the welfare of (tribal) people, but after Prime Minister Modi came to power in 2014, funds for tribal uplift were enhanced to Rs 78,000 crore, Shah said.

Home Minister Amit Shah during a roadshow in Bhopal on Friday PIC/PTI

The home minister was speaking at `Van Samiti Sammelan', a programme where bonus was distributed to collectors of forest produce such as tendu leaves (used to wrap bidis - an Indian version of cigarette) and forest societies.

On the occasion, he also unveiled a plaque announcing the change of status of 827 `forest villages' into `revenue villages'. There was a demand that these areas be declared revenue villages to ensure their development as there are restrictions on undertaking projects in forest areas.

Terming the decision as historic, the Union minister said it fulfilled a long-pending demand. Around Rs 123 crore was distributed as bonus to 12 lakh tendu leaf pluckers, bamboo growers and other forest produce societies.

According to an estimate, there were around 35 lakh tendu pluckers in Madhya Pradesh.

Tendu (diospyros melanoxylon) leaf collection is one of the major economic activities of tribals in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. Tendu leave collections generate 150 million person days of employment during the agricultural lean season.

This was the second tribal outreach by Shah in just over 6 months in the BJP-ruled Madhya Pradesh, where Assembly polls are due in 2023 and the ruling party appears keen to woo the indigenous people, who form a major chunk of voters.

On September 18, Shah had addressed 'Gaurav Utsav', an event organised in honour of tribal icons and erstwhile Gondwana empire ruler Shankar Shah and his son Raghunath in Jabalpur district.

Shah's programme on Friday was held at Bhopal's Jamboree Ground, the venue where Prime Minister Narendra Modi had addressed a mega tribal gathering on Janjatiya Gaurav Diwas, the birth anniversary of revered tribal icon Birsa Munda on November 15.

प्री-इवेंट कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

Print Media

ग्राम वन समिति ने ग्राम आवर में आवंटित क्षेत्र को घास बीड़ के रूप में किया विकसित

आगर मालवा 20 अप्रैल। आगर मालवा जिले में वन विभाग

द्वारा जिले के ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है, जो कि वनों को विकसित कर उनका संरक्षण करने के साथ ही ग्राम विकास के कार्य भी करती है।

आगर मालवा जिला मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम आवर जहां वन विभाग द्वारा ग्राम वन समिति का गठन किया गया है। फॉरेस्ट विभाग द्वारा आवर ग्राम वन समिति को क्ष्क्ष-46 रकबा 100 हेक्टेयर संयुक्त वन प्रबंधन हेतु आवंटित किया गया है। ग्राम वन समिति के सचिव वनरक्षक श्री पदम् परमार एवं सदस्य दिलीप सिंह परमार बताते हैं कि समिति द्वारा उक्त आवंटित क्षेत्र को घास बीड़ के रूप में विकसित किया गया है। विकसित बीड़ की देखरेख ग्राम वन समिति द्वारा की जाती है। आज इस क्षेत्र में पर्याप्त चारे की पैदावार होती है जो कि पशुओं का मुख्य आहार होता है। ग्राम वन समिति घास बीड के चारे को समीप स्थित गौशालाओं को प्रतिवर्ष नीलामी कर उपलब्ध करवाती है।सर्वाधिक चारा निर्धारित शुल्क में माधव गोशाला आगर में दिया जाता हैं। जिससे समिति को प्रतिवर्ष अच्छा लाभ प्राप्त होता है। वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक समिति को चारा नीलामी से कुल 5 लाख 95 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है। समिति द्वारा प्राप्त लाभ की राशि का उपयोग घास बीड की सुरक्षा और विभिन्न ग्राम विकास के कार्यों में किया जाता है।

बिगड़े वन क्षेत्रों को सुधारने में सफलता मिली

करारा जवाब » सागर

सागर जिले के दक्षिण वन मण्डल के वन परिक्षेत्र राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम वन समिति टीला बुजुर्ग ने बिगड़े वन क्षेत्रों को सुधारने में अभूतपूर्व कार्य किया है। जिसका परिणाम है कि उस क्षेत्र में हरे-भरे जंगल दिखाई दे रहे है।

संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विभाग के संयुक्त रूप से कड़ी मेहनत से बिगड़े वनों को सुधारा जा सका। ग्राम वन समिति टीला बुजुर्ग अपने रकबे के साथ-साथ लगभग 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुरक्षा का कार्य करती है।

समिति द्वारा सुरक्षित किए गए वन क्षेत्र में तेंदूपत्ता, अचार, महुआ आदि का संग्रहण भी ग्राम वासियों द्वारा किया जाता है। वन समिति के अध्यक्ष श्री हेमेष सिंह राजपूत तथा समिति की उपाध्यक्ष गुड्डीबाई लोधी, समिति के सदस्यों को वन सुधार के लिए लगातार प्रेरित

करते है। समय-समय पर ग्राम वन समिति की बैठक का आयोजन वन विभाग के सामंजस्य से किया जाता है। सदस्यों के बीच लगातार संवाद बनाए रखते है। वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर नवीन गर्ग एवं अधीनस्थ अमला वन समिति के सदस्यों के साथ सतत संवाद बनाए रखता है। इससे यदि समिति के समक्ष आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

प्री-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पर्वतपुरा बीट में कार्य कर रही है दो वन समितियाँ राशन की दुकान भी करते है संचालित

स्वतंत्र समय, धार।

जिले के पर्वतपुरा बीट में अंजनाई व सेमलीपुरा ग्राम वन समितियाँ है। इन दोनों समिति के माध्यम से समिति के सदस्य राशन की दुकान भी संचालित करते हैं, सभी लाभार्थी वहाँ से राशन प्राप्त करते है। इसके अलावा वन विभाग के वर्किंग प्लान के अनुसार डेव्लपमेंट गतिविधि भी की जाती है। जिसमें समितियों की सक्रिय भागीदारी होती है। जंगल में आगजनी होने पर समितियों का पूरा सहयोग किया जाता है। समितियों के सदस्य आग बुझाने में पूरी मदद करते है। रात्रि गश्ती या अन्य कारणों से वन स्टॉफ जब आता है इस कार्य में भी वन समिति के सदस्यों का सहयोग रहता है। इस प्रकार जंगलो का विकास वन विभाग व ग्राम वन समिति के माध्यम से देखने को मिलता है। ज्ञात हो कि वनमण्डल धार के वनक्षेत्र में वानिकी प्रजातियों की लगभग 50 प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती है जिनमें अधिकांश प्रजातियों में प्रतिवर्ष पुष्पन, फलन एवं बीज उत्पादन होता है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष रोपण हेतु वानिकी प्रजातियों का बीज क्रय किया जाता है जो संभवतः वनक्षेत्रो से ही संग्रहित किया जाता है।

स्थानीय महत्व की वानिकी प्रजातियों को सूचीबद्ध कर उनके पुष्पन, फलन, बीज तैयार होने, बीज संग्रहण की अवधि, प्रतिकिलो बीज की संख्या, अंकुरण क्षमता, बीज उपचार, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन मात्रा, संग्रहण की पद्धति का प्रायोगिक अध्ययन कर वनमण्डल की समस्त सातो परिक्षेत्रो में स्थानीय अमले द्वारा बीज संग्रहण कार्य किया जाता है । परिक्षेत्र मुख्यालय स्तर पर प्रतिदिन संग्रहित बीज की प्रजाति, मात्रा संग्रहण कार्य, संग्रहण स्थल की प्रतिदिन प्रविष्ठी की जाती है। संग्रहित बीज के फलों फलियों को सुखाकर, आवश्यक उपचार कर, शुद्ध बीज प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार रोपण हेतु तैयार बीज की मात्रा का भी प्रजातिवार रिकार्ड तैयार किया जाता है। बीजारोपण हेतु उपयुक्त वृक्षारोपण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र को सूचीबद्ध किया जाता है। प्रत्येक स्थलवार पशु अवरोधक खंती ,कन्टूर ट्रेंच, सतत कन्टूर ट्रेंच, जल संचयन संरचना एवं मिट्टी चेकडेम की मात्रा की गणना कर आवश्यक बीज का आंकलन किया जाता है। इस प्रकार स्थलवार आवश्यक बीज का प्रजातिवार बटवारा कर स्थानीय अमले को रोपण विधि, अवधि से अवगत कर आवंटित किया जाता है। आवंटन के पूर्व पशु अवरोधक खंती की मेढ़ पर रोपित की जाने वाली प्रजातियों - प्रोसेपिस, बबूल, खैर, बैर, कस्टार, रिंझा के बीजो का समान अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है।

वृक्षारोपण क्षेत्रो में मृत पौधो के स्थान पर खाली गड्ढो में बीजारोपण हेतु चयनित प्रजातियों - सीताफल, महुआ, बेहड़ा, चिरोंल, सीसु, ईमली, जंगल जलेबी, साजा, सिरस, महारूख आदि को पृथक-पृथक आवंटन किया जाता है। उपचारित क्षेत्रो में निर्मित कन्टूर ट्रेंच ,सतत कन्टूर ट्रेंच ,जल संचयन संरचना की मेढ़ एवं मिट्टी चेकडेम की मेढ़ हेतु शेष संग्रहित समस्त प्रजातियों का मिश्रण तैयार कर वितरित किया जाता है। रोपण के लिए पशु अवरोधक खंती की मेढ़ पर मिट्टी में तीन लाईनो में हंसिये/गैती से खोदकर 15 से.मी. के अन्तराल पर मिश्रित प्रजाति के एक-एक बीज का रोपण किया जाता है। खैर, प्रोसोपिस, बबूल, कस्टार, रिंझा आदि प्रजातियों के मिश्रण में 20 से 30 हजार बीज प्रति किलो आते है। तीन लाईनों में बुवाई करने पर एक किलोग्राम बीज 500 र.मी. हेतु पर्याप्त होगा। इसी प्रकार उपचारित संरक्षित क्षेत्रो में निर्मित कन्टूर टेंऊच सतत कन्टूर ट्रेंच, जल संचयन संरचना की मेढ़ की मिट्टी में हंसिये/गैती से तीन लाईनों में 15 से.मी. के अन्तराल में मिश्रित प्रजातियों को रोपण किया जाता है।

कुलुवा में पहले जंगल की स्थिति बंजर थी धीरे-धीरे जंगल हरियाली में परिवर्तित हुआ फिर स्थिति बहुत अच्छी हुई

जंगल में सम्मेलन किया गया यहां पर 8 हजार लोग एकत्रित हुए जिसमे से 5 हजार लोगों ने संकल्प लिया: ना हम जंगल काटेंगे और ना ही किसी को काटने देंगे, अब यहा हरियाली और पेड़ ही पेड़ दिख रहे

दमोह (विंध्य सत्ता)

ग्राम वन समिति के पूर्व अध्यक्ष रूपलाल मिश्रा कहते है पहले मैं ग्राम पंचायत कुलुआ का सरपंच था, उस समय सरपंच पद ग्रहण करने के बाद सभा हुई, उस सभा में कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि आप सरपंच बन गए हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि मै क्षेत्र की भूमि का भौगोलिक नक्शा तैयार करूंगा, इस भौगोलिक वन क्षेत्र में कितने गांव आते हैं, इस क्षेत्र पर कितने गांव का दबाव है का आंकलन करने सबसे पहले मैंने इस भौगोलिक क्षेत्र का वन विभाग के नक्शे से कक्ष क्रमांक 417, 418, 419, 420, 421, 422 एवं 425 में इसका सर्वे करवाया तो यह रिजल्ट आया कि यहां 3668 हेक्टेयर वन भूमि थी।

वे कहते हैं उस समय मुझे लोगों की अच्छी उत्सुकता दिखी कि हम जंगल बचाएं। मैंने सभी से प्रश्न किया कि सभी लोग सहयोग करेंगे तो पंचायत के माध्यम से समिति बनाऐंगे, आप सभी वनों की सुरक्षा करना और जंगल बना लेना, यह जंगल सभी के काम में आएगा। बहुत सी चीजें जंगल में उपयोगी होंगी, जिससे आपकी आय बढ़ जाएगी और 3668 भूमि पर 12 समितियां गठित की गई। इसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उस समय वन मंत्री जी, वन विभाग से सीसीएफ और अधिकारी आए, तब समिति के लोगों से शपथ कराई कि न हम पर पेड़ काटेंगे और ना ही किसी को पेड़ काटने देंगे। हर समिति में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई पेड़ काटता है तो उसका 100 जुर्माना कर-

के समिति में जमा करेंगे। यदि साइकिल पर पेड़ काट कर ले जाता है तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा और साईकिल जब्त करके साईकिल की नीलामी समिति करेगी, उसकी जो आय होगी वह समिति में जाएगी।

तब से लोगों में एक बहुत बड़ी जागरूकता आई, सबसे पहले यहां पर 200 से 300 एकड़ भूमि में अतिक्रमण था आसपास के गांवों में अतिक्रमण को हटाया यह पूरा क्षेत्र वनविहीन था। संकल्प लिया गया कि इस भूमि को सघन वन बनाना है। सभी सहयोगी ग्रामीणों ने महिलाओं से लेकर पुरुषों और बच्चों ने संकल्प लिया कि वृक्षों को नहीं काटेंगे। धीरे-धीरे यह सघन वन बन गया। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत समिति कुलुवा को पुरस्कृत किया गया।

उन्होंने बताया 40 हेक्टेयर भूमि में इसको मिश्रित वन घोषित करवा कर इसमें वृक्षारोपण का कार्य करवाया, जब इसका रिजल्ट अच्छा आया तो 2015 में फिर से प्लांटेशन करवाया फिर सोचा जितना ज्यादा प्लांटेशन करवा लेंगे तो गांव के लोगों को गड्ढा खोदने में, पौधा लगाने में, चौकीदारी करने एवं वन के चारों तरफ तार फेंसिंग करने में रोजगार मिलेगा, जंगल की सफाई होगी उसमें भी रोजगार मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर यहां पर 6 प्लांटेशन तैयार करवाए।

उन्होंने कहा कुलुवा में पहले जंगल की स्थिति बंजर थी धीरे-धीरे जंगल हरियाली में परिवर्तित हुआ फिर स्थिति बहुत अच्छी हुई, उस समय जंगल में सम्मेलन किया गया यहां पर 8 हजार लोग एकत्रित हुए थे जिसमें से 5 हजार लोगों ने संकल्प लिया कि ना हम जंगल काटेंगे और ना ही किसी को काटने देंगे साथ ही अपने खेतों में भी पेड़ लगाऐंगे। सर्वप्रथम यहां 40 हेक्टेयर में मिश्रित प्लांटेशन लगाया गया।

कुलुवा निवासी श्री राजपूत ने कहा कुलुवा समिति की यह खास जमीन हैं। इस जंगल में जानवर भी रहते हैं, पहले यहां पर कुछ नहीं था। पंडित जी ने मेहनत की और सभी लोगों का सहयोग रहा जिससे यह जंगल बना इसमें जो जानवर हैं और जो भी लाभदायक पेड़ आंवला और भी अन्य पेड़ लगवाए गये है जिससे हम लोगों को भी फायदा है। जंगल से गायों के लिए घास मिल रही है।

कुलुवा में पदस्थ बीट गार्ड पवन सिंह ठाकुर ने कहा यहा पर 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन हैं। यहा पर पेड़ो की कई प्रजातियां लगाई गई है, मिश्रित वृक्षारोपण है। वृक्षे में यहा पर आंवला, शीशम, नीम, सागौन, करंज, खमेर, महुआ, कोहा, जामुन एवं अन्य प्रकार के पेड़ लगाए गये हैं। यहा पर हरियाली के कारण जानवर भी आ गये हैं। जानवरों में यहा जंगली सुअर, छिकरा, हिरण खरगोश एवं नीलगाय है।

कुलुवा निवासी एवं बीट सदस्य दुर्गा सिंह ठाकुर ने कहा हम लोगों ने रात और दिन बहुत मेहनत करके इस जंगल को बनाया है। रात में भी जंगल की निगरानी की है, यदि कोई रात में पेड़ काटता था तो उसे पकड़ने के लिए जाते थे। पहले यहा पर कुछ नहीं था, पंडित जी के मार्गदर्शन में मेहनत की आज यहा पर हरियाली है और जानवरों की प्रजातिया भी हैं।

प्री-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

सफलता की कहानी

वन समिति ने दमोह जिले के कुलुवा गांव की बंजर जमीन में फैलायी हरियाली

भोपाल (आरएनएन)। दमोह जिले में ग्राम कुलुवा की बंजर जमीन अब हरे.भरे पेड़ों से आच्छादित है। यह संभव हुआ हैए वन समितियों के दृढ़ निश्चय और सकारात्मक प्रयासों से। समिति के सदस्यों ने न हम पेड़ काटेंगे और न काटने देंगे के संकल्प को पूरी तन्मयता से निभाया। समिति ने तय किया है कि कोई भी पेड़ काटेगा तो 100 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। साइकिल पर पेड़ काटकर ले जाने वालों को 500 रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा और साइकिल जब्त कर समिति उसकी नीलामी की जायेगी। ग्राम वन समिति में पूर्व अध्यक्ष श्री रूपलाल मिश्रा ने बताया कि जब मैं सरपंच बना तोए क्षेत्र का सर्वे करवाया। सर्वे में 3668 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गयी। फिर ग्रामीणों के साथ राय.मशविरा कर पौधे लगाने और पेड़ों के बचाने की रूपरेखा बनी। सर्वसहमति से बनी रूपरेखा का क्रियान्वयन करने के लिए 12 समितियां गठित की गयी। समितियों ने सर्वप्रथम 40 हेक्टेयर में मिश्रित प्लांटेशन किया। इसके बाद यह क्रम लगातार जारी रहा। प्लांटेशन के लिए गड्ढा खोदने, फेंसिंग करने आदि कार्यों में ग्रामीणों को लगाया गयाए जिससे उन्हें रोजगार भी प्राप्त हुआ। कुलुवा में पदस्थ बीट गार्ड पवन सिंह ठाकुर ने बताया कि यहां पर 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन है। पेड़ो की कई प्रजातियां लगाई गई हैं और मिश्रित पौधरोपण हैं। आंवलाए शीशम, नीम, सागौन, करंज, खामेर, महुआ, कोहा, जामुन एवं अन्य प्रकार के पेड़ लगाये गये हैं। यहां पर हरियाली के कारण जंगली सूअर, छिकरा, हिरण, खरगोश एवं नीलगाय विचरण करती देखी जा सकती हैं।

पर्वतपुरा बीट में कार्य कर रही है दो वन समितियाँ, राशन की दुकान भी करते है संचालित

धार।

जिले के पर्वतपुरा बीट में अंजनाई व सेमलीपुरा ग्राम वन समितियां है। इन दोनों समिति के माध्यम से समिति के सदस्य राशन की दुकान भी संचालित करते हैं, सभी लाभार्थी यहीं से राशन प्राप्त करते हैं। [illegible]

[illegible]

नवभारत

लखनी में 54 हेक्टेयर में वन हो गया तैयार

जन-सहभागिता से काम ऐसे हो जाते

नवभारत, दमोह. जन-सहभागिता से काम ऐसे हो जाते है कि देखकर लोग चकित हो जाते है। जी हां चर्चा कर रहे है एक ऐसे ग्राम की जहां गांव के लोगों ने संकल्पित होकर वन रोपिणी का काम किया और आज 50 हजार से अधिक पौधे बड़े होने लगे है और लह-लहा रहे हैं। उनका वनो के संरक्षण और उनके विकास की यह अद्भुत प्रयास है। इनके इन प्रयासो की हर जगह प्रशंसा भी हो रही है।जिले के ग्राम लखनी में 54 हेक्टर क्षेत्र में ग्राम वन समिति द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। इस संबंध में वन समिति के रूप नारायण दुबे ने बताया इसमें कई प्रजातियों के पौधा रोपण किया गया। 16000 सागौन, का पौधा रोपण किया गया ढाई हजार आंवले का पेड़, 4000 महुआ, 270 चिरौंजी, 766 पौधे शीशम के और 3000 अन्य पौधे ढाई हजार नीम के पौधे लगाए गए इसके बाद कंज भी लगाई गई आंवला भी लगाया गया 1300 बहेरा के पौधे लगाए गए जो हमारी औषधि के काम में आ जाता है उसके लिए उसके बाद नई तकनीकी से बेरी के पौधा ढाई हजार लगाए गए हैं कुल मिलाकर लगभग इसमें 16 प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया उन्होंने बताया पौधा लगाने के पहले मेरे मन में विचार आया यहां पर इस मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए तत्पश्चात इसका पौधों का रोपण किया जाएगा क्योंकि यहां बहुत पहले महुआ अचार पापड़ा छेवला यह सारी प्रजातियां पहले मौजूद थी और सब कट चुकी थी उसी आधार पर यहां पर हर प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदे की बात है यहां पर जो मजदूर हैं तेंदूपत्ता से यहां पर जीवन यापन कर रहे हैं और यहां पर तेंदूपत्ता की भी सुरक्षा हो गई उससे उनको बहुत लाभ होता है। बाद में यहां पर 4000 महुआ के पेड़ लगाए गए भविष्य में महुआ से आए होने लगेगी आज वर्तमान में 80 रूपये किलो बिक रहा है।यहां पर तालाब है जानवर भी आते है खरगोश भी आ जाते है वहा पर पानी की अच्छी व्यवस्था भी है. ग्राम वन समिति के चौकीदार कहते हैं यहाँ पर जाली लगी हुए है जिससे कोई जानवर ना आ पाये और जानवर के सींग जाली मे ना बुंदे उसके लिए जाच भी करनी पडती है।

प्री-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

रीवा, शुक्रवार, 22 अप्रैल 2022 स्टार समाचार

वन समिति ने जन सहयोग से 20 हजार से अधिक वृक्षों को किया तैयार

स्टार समाचार | रीवा

मानव के जीवन चक्र में वनों और वनस्पतियों का बहुत महत्व है। पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण के लिए भी वनों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। इस उद्देश्य से वन विभाग द्वारा 1995 से संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की गईं। रीवा जिले के डभौरा रेंज में आदिवासी बहुल ग्राम गेंदुरहा में संयुक्त वन समिति ने जन सहयोग से वनों की सुरक्षा और संरक्षण का शानदार कार्य किया है।

वन विभाग तथा वन समिति के लगातार प्रयासों से 20 हजार से अधिक हरे-भरे वृक्ष तैयार किए गए हैं। समिति ने 30 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को हरा-भरा बना दिया है। जिस स्थान पर छोटी झाड़ियों और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ हरे-भरे वृक्ष लहरा रहे हैं।

वन प्रबंधन तथा संरक्षण के संबंध में वन समिति के अध्यक्ष बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को गेंदुरहा में मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। समिति के अधिकांश सदस्य आदिवासी हैं जो वर्षों से आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। उन्हें प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण कराया गया। वन विभाग में गांव में हैण्डपंप तथा आदिवासी मोहल्ले में चबूतरे का निर्माण जैसे आस्थामूलक कार्य करके लोगों का विश्वास जीता। वन समिति ने वन विभाग के सहयोग से पूरे क्षेत्र में छोटे नालों पर कई बोल्डर चेक डैम बनाए। इनसे एक ओर मिट्टी का कटाव रूका वहीं दूसरी ओर पेड़-पौधों और वन्य प्राणियों के लिए पानी भी उपलब्ध हुआ।

वनों को सुरक्षित करने किया गया प्रयास

वन समिति ने नए पौधे तैयार करने के साथ वन में मौजूद पुराने वृक्षों की देखभाल और सुरक्षा पर ध्यान दिया। आदिवासी परिवार अप्रैल और मई में महुआ बीनने जाते हैं। उनकी आमदनी का महुआ प्रमुख जरिया है। महुआ संग्रहण को व्यवस्थित तथा वनों को सुरक्षित करने का प्रयास समिति द्वारा किया गया। परिवारों को महुआ के पेड़ आवंटित कर दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा, देखभाल एवं उनसे मिलन वाले महुआ फूल पर आदिवासी परिवार का ही हक बनाए रखा गया। इससे महुआ बीनने के समय होने वाली आगजनी की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगी। वन समिति के सदस्यों की जागरूकता, आमजनता के सहयोग तथा वन विभाग की सक्रियता से वृक्षों की अवैध कटाई एवं अवैध उत्खनन पर भी पूरी तरह से रोक लगाने में समिति को सफलता मिली। गेंदुरहा वन समिति संयुक्त वन प्रबंधन का शानदार उदाहरण है।

दै. राज एक्सप्रेस
22 APR 2022

मप्र में वन समितियों ने संरक्षण की दिशा में किया शानदार काम

भोपाल, (प्रस)। मध्यप्रदेश में सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन, संरक्षण एवं सुधार की दिशा में वन समितियों के माध्यम से शानदार काम किया गया है जो पूरे देश में अनूठा है। इन वन समितियों से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से भी सशक्त हुए हैं।

प्रदेश का वनक्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह देश के कुल वन क्षेत्र का 12.3 प्रतिशत है। प्रदेश के 79 लाख 70 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रबंधन में जन-भागीदारी के लिए 15,608 गांवों में वन समितियां काम कर रही है। पिछले एक दशक में 1552 गांवों में वन समितियों ने 4 लाख 31 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुधार किया है। जब पूरी दुनिया में वनों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय इन समितियों ने वन विभाग के साथ मिलकर शानदार काम किया है।

राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, वनोपज संग्रहण करने वाले परिवारों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। संघ के क्रांतिकारी कदमों से तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में

लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार

सकारात्मक बदलाव आया है। तेंदूपत्ता सीजन में 2021 कोविड 19 के कारण लॉकडाउन के बाद भी तेंदूपत्ता संग्रहण कराकर दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय परिवारों को 415 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक दिलाया गया और 192 करोड़ का लाभांश भी वितरित किया गया। पुरानी नीति में 70 फीसदी लाभांश संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाता था। साथ ही 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए और 15 प्रतिशत राशि वन क्षेत्रों में लघु वन उपज देने वाली प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास पर खर्च की जाती थी। अब पेसा अधिनियम की भावना के अनुसार तेंदूपत्ता के व्यापार से होने वाले लाभ का 75 प्रतिशत संग्राहकों को, 10 प्रतिशत राशि संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए और 10 प्रतिशत राशि वन क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के संरक्षण तथा 05 प्रतिशत ग्राम सभाओं को दी जाएगी। वन विभाग द्वारा नए संकल्प में राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के प्रवेश से मिलने वाली राशि का 33 प्रतिशत वन समितियों को देने का प्रावधान किया गया है। समितियों को आवंटित क्षेत्र में ईको पर्यटन का कार्य संचालित करने के लिए सक्षम किया गया है। इससे होने वाली आय वन समिति को मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के अवसर मिलेंगे।

वन समितियों का माइक्रो प्लान

प्रदेश के एक तिहाई गांव वन क्षेत्रों के अंदर या उसके आसपास बसे हैं। यहां के निवासियों की आजीविका वनों पर आधारित है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में इस साल के आखिर तक 5000 वन समितियों का माइक्रो प्लान तैयार करने का लक्ष्य है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ग्राम समुदाय अपनी आवश्यकता की वनोपज का उत्पादन कर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

लाभांश में वृद्धि

वन समितियों को दिए जाने वाले लाभांश में वृद्धि की गई है। पहले जिला स्तर पर शुद्ध लाभ की राशि का 20 फीसदी मिलता था, जिसकी वजह से राशि का वितरण केवल कुछ ही जिलों में हो पाता था। अधिकांश समितियां लाभ से वंचित रह जाती थीं। नए संकल्प के अनुसार प्रत्येक समिति को उसके क्षेत्र में से किए गए दोहन से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पहले काष्ठ एवं बांस का 50 करोड़ रुपए तक का लाभांश वितरण होता था। अब लगभग 160 करोड़ प्रति वर्ष हो रहा है।

ग्राम सभाओं को सौंपा अधिकार

वन समितियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का अधिकार अब ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। वन समिति की कार्यकारिणी में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लोगों को शामिल करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में अनेक प्रकार की वनोपज का उत्पादन होता है। इनमें महुआ, तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और चिरौंजी प्रमुख है। पेसा कानून की भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों का पूरा अधिकार सौंपा गया है।

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में लगातार वृद्धि की गई है। इसी के अनुपात में पारिश्रमिक और बोनस का भुगतान भी किया गया है। संग्रहण दर वर्ष 2005 में प्रति मानक बोरा 400 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा हो गई है। पारिश्रमिक का भुगतान वर्ष 2005 में 67 करोड़ रुपए होता था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 415 करोड़ रुपए हो गया है।

प्री-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

22 APR 2022 भोपाल

वन ग्राम समिति की मेहनत से लौट रहा है वनों का खोया वैभव

लोकोत्तर समाचार सेवा ■ भोपाल
www.elokottar.in

वन विभाग ने माइक्रो प्लानिंग कर ग्राम वन समितियों के सहयोग से जंगलों की बहाली पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं। मंडला जिले का मनेरी वन ग्राम स्टाक मेपिंग (वर्ष 2004-14) क्षेत्र वनस्पति से रहित था और आरडीएफ (वन पुनर्घनत्वीकरण) के लिये चुना गया था। मनेरी ग्राम वन समिति का गठन कर उसे 186.92 हेक्टेयर वन प्रबंधन का काम सौंपा गया था। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास होने के कारण यह वन क्षेत्र गंभीर जैविक दबाव में था। बावजूद इसके स्थानीय समुदायों ने अवैध कटाई और चराई के खिलाफ वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2003-4 और 2005-6 के बीच यहाँ जंगल बहाली का काम शुरू हुआ। इस काम में ग्राम वन समिति मनेरी का नेतृत्व कर रही महिला सुश्री कल्लू बाई मार्को ने वन संरक्षण और प्रबंधन के लिये समुदाय को संगठित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। ग्राम वन समुदाय के अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प के चलते आज यह क्षेत्र वन से बहाल हो गया है।

इतना ही नहीं, बीते 2 सालों में समुदाय ने 3 हजार 526 सागौन और 31 ईंधन के ढेर की कटाई कर लाभ भी कमाया है।

जनजातीय ग्राम वन समिति ने बहाल किया 192 हेक्टेयर में जंगल : वन विभाग ने स्थानीय समुदायों की वन प्रबंधन और उनकी बहाली में शामिल करते हुए प्रदेश के खाली वन क्षेत्रों को वन सम्पदा से समृद्ध करने में कामयाबी हासिल की है। डिंडौरी जिले की बड़ी नालदी ग्राम वन समिति को लगभग 15 साल पहले 192 हेक्टेयर खाली वन क्षेत्र को बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ग्राम वन समिति के सदस्य और ग्रामीणों द्वारा सालों से किये गये अथक प्रयासों से इस क्षेत्र का वन वैभव पुनः लौट आया है। जनजातीय समुदाय की आजीविका में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन की बहाली से आजीविका के संसाधन भी बढ़ने लगे हैं। वनों के कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र में भी असंतुलन जैसी जलवायु समस्याएँ भी उत्पन्न होती है। वनों की बहाली से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक उचित और स्थायी समाधान मिल गया है।

सफलता की कहानी : 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन, पेड़ों की कई प्रजातियां लगाई

वन समिति ने दमोह जिले के कुलुवा गांव की बंजर जमीन में फैलाई हरियाली

सत्ता सुधार ■ भोपाल

दमोह जिले में ग्राम कुलुवा की बंजर जमीन अब हरे-भरे पेड़ों से आच्छादित है। यह संभव हुआ है, वन समितियों के दृढ़ निश्चय और सकारात्मक प्रयासों से। समिति के सदस्यों ने 'न हम पेड़ काटेंगे और न काटने देंगे' के संकल्प को पूरी तन्मयता से निभाया। समिति ने तय किया है कि कोई भी पेड़ काटेगा तो 100 रुपए जुर्माना लगाया जायेगा। साइकिल पर पेड़ काटकर ले जाने वालों को 500 रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा और साइकिल जब्त कर समिति उसकी नीलामी की जायेगी।

ग्राम वन समिति में पूर्व अध्यक्ष श्री रूपलाल मिश्रा ने बताया कि जब मैं सरपंच बना तो, क्षेत्र का सर्वे करवाया। सर्वे में 3668 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गयी। फिर ग्रामीणों के साथ राय-मशविरा कर पौधे लगाने और पेड़ों के बचाने की रूपरेखा बनी। सर्वसहमति से बनी रूपरेखा का क्रियान्वयन करने के लिए 12 समितियां गठित की गयी। समितियों ने सर्वप्रथम 40 हेक्टेयर में मिश्रित प्लांटेशन किया। इसके बाद यह क्रम लगातार जारी रहा। प्लांटेशन के लिए गड्ढा खोदने, फेंसिंग करने आदि कार्यों में ग्रामीणों को लगाया गया, जिससे उन्हें रोजगार भी प्राप्त हुआ।

कुलुवा में पदस्थ बीट गार्ड पवन सिंह ठाकुर ने बताया कि 'यहां पर 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन है। पेड़ों की कई प्रजातियां लगाई गई हैं और मिश्रित वृक्षारोपण है। आंवला, शीशम, नीम, सागौन, करंज, खामेर, महुआ, कोहा, जामुन एवं अन्य प्रकार के पेड़ लगाये गये हैं। यहाँ पर हरियाली के कारण जंगली सूअर, छिकरा, हिरण, खरगोश एवं नीलगाय विचरण करती देखी जा सकती हैं।'

प्री-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

विंध्य भारत
vindhyabharat.in
रीवा, शुक्रवार 22 अप्रैल 2022

वन समिति ने जन सहयोग से 20 हजार से अधिक वृक्षों को किया तैयार

◆ संयुक्त वन प्रबंधन से बदली तस्वीर – 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तैयार हुआ जंगल

विंध्य भारत, रीवा

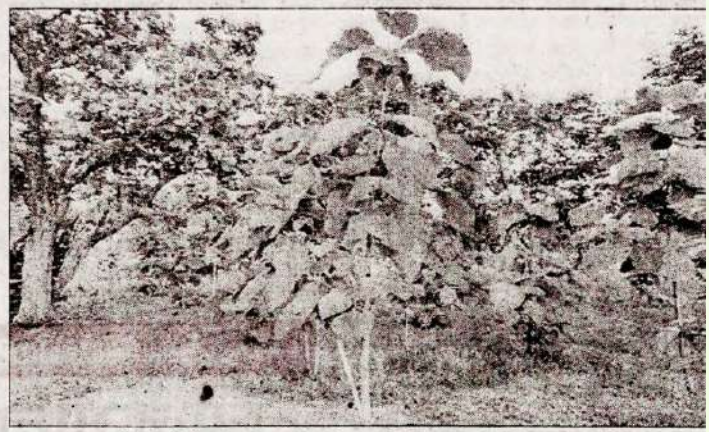

मानव के जीवन चक्र में वनों और वनस्पतियों का बहुत महत्व है। पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण के लिए भी वनों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। इस उद्देश्य से वन विभाग द्वारा 1995 से संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की गई। रीवा जिले के डभौरा रेंज में आदिवासी बहुल ग्राम गेंदुरहा में संयुक्त वन समिति ने जन सहयोग से वनों की सुरक्षा और संरक्षण का शानदार कार्य किया है। वन विभाग तथा वन समिति के लगातार प्रयासों से 20 हजार से अधिक हरे-भरे वृक्ष तैयार किए गए हैं। समिति ने 30 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को हरा भरा बना दिया है। जिस स्थान पर छोटी झाड़ियों और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ हरे-भरे वृक्ष लहरा रहे हैं।

वन प्रबंधन तथा संरक्षण के संबंध में वन समिति के अध्यक्ष बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को गेंदुरहा में मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। समिति के अधिकांश सदस्य आदिवासी हैं जो वर्षों से आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। उन्हें प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण कराया गया। वन विभाग में रात में हैण्डपंप तथा आदिवासी मोहल्ले में चबूतरे का निर्माण जैसे आस्थामूलक कार्य करके लोगों का विश्वास जीता। वन समिति ने वन विभाग के सहयोग से पूरे क्षेत्र में छोटे नालों पर कई बोल्डर चेकडैम बनाए। इससे एक ओर मिट्टी का कटाव रुका वहीं दूसरी ओर पेड़-पौधों और वन्य प्राणियों के लिए पानी भी उपलब्ध हुआ।

वन समिति ने नए पौधे तैयार करने के साथ वन में मौजूद पुराने वृक्षों की देखभाल और सुरक्षा पर ध्यान दिया। आदिवासी परिवार अप्रैल और मई में महुआ बीनने जाते हैं। उनकी आमदनी का महुआ प्रमुख जरिया है। महुआ संग्रहण को व्यवस्थित तथा वनों को सुरक्षित करने का प्रयास समिति द्वारा किया गया। परिवारों को महुआ के पेड़ आवंटित कर दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा, देखभाल एवं उनसे मिलने वाले महुआ फूल पर आदिवासी परिवार का ही हक बनाए रखा गया। इससे महुआ बीनने के समय होने वाली आगजनी की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगी। वन समिति के सदस्यों की जागरूकता, आमजनता के सहयोग तथा वन विभाग की सक्रियता से वृक्षों की अवैध कटाई एवं अवैध उत्खनन पर भी पूरी तरह से रोक लगाने में समिति को सफलता मिली। गेंदुरहा वन समिति संयुक्त वन प्रबंधन का शानदार उदाहरण है।

प्री-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश की वन समितियों ने किया शानदार काम

लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार

स्वतंत्र समय, भोपाल।

मध्यप्रदेश में सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन, संरक्षण एवं सुधार की दिशा में वन समितियों के माध्यम से शानदार काम किया गया है जो पूरे देश में अनूठा है। इन वन समितियों से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से भी सशक्त हुए हैं। प्रदेश का वनक्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर है जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह देश के कुल वन क्षेत्र का 12.3त्न है। प्रदेश के 79 लाख 70 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रबंधन में जन-भागीदारी के लिये 15 हजार 608 गाँवों में वन समितियाँ काम कर रही है। पिछले एक दशक में 1552 गाँवों में वन समितियों ने 4 लाख 31 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुधार किया है। जब पूरी दुनिया में वनों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय इन समितियों ने वन विभाग के साथ मिलकर शानदार काम किया है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, वनोपज संग्रह करने वाले परिवारों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। संघ के नवाचारी उपायों से तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। तेंदूपत्ता सीजन में 2021 कोविड-19 के कारण लॉक-डाउन के बाद भी तेंदूपत्ता संग्रहण कराकर दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय परिवारों को 415 करोड़ रूपये का पारिश्रमिक दिलाया गया और 192 करोड़ का लाभांश भी वितरित किया गया। पुरानी नीति में 70 फीसदी लाभांश संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाता था। साथ ही 15त्न राशि संग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए और 15त्न राशि वन क्षेत्रों में लघु वन उपज देने वाली प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास पर खर्च की जाती थी। अब +पेसा अधिनियम+ की भावना के अनुसार तेंदूपत्ता के व्यापार से होने वाले लाभ का 75त्न संग्राहकों को, 10त्न राशि संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए और 10त्न राशि वन क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के संरक्षण तथा 5 प्रतिशत ग्राम सभाओं को दी जाएगी। वन विभाग द्वारा नए संकल्प में राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के प्रवेश से मिलने वाली राशि का 33त्न वन समितियों को देने का प्रावधान किया गया है । समितियों को आवंटित क्षेत्र में ईको पर्यटन का कार्य संचालित करने के लिए सशक्त किया गया है। इससे होने वाली आय वन समिति को मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने के अवसर मिलेंगे।

लाभांश में वृद्धि

वन समितियों को दिए जाने वाले लाभांश में वृद्धि की गई है। पहले जिला स्तर पर शुद्ध लाभ की राशि का 20 फीसदी मिलता था, जिसकी वजह से राशि का वितरण केवल कुछ ही जिलों में हो पाता था। अधिकांश समितियाँ लाभ से वंचित रह जाती थी। नए संकल्प के अनुसार प्रत्येक समिति को उसके क्षेत्र में से किए गए दोहन से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पहले काड एवं बाँस का 50 करोड रूपए तक का लाभांश वितरण होता था। अब लगभग 160 करोड़ प्रति वर्ष हो रहा है।

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में लगातार वृद्धि की गई है। इसी के अनुपात में पारिश्रमिक और बोनस का भुगतान भी किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2005 में प्रति मानक बोरा ?400 थी, जो अब बढ़कर 2500 सौ रूपये प्रति मानक बोरा हो गई है। पारिश्रमिक का भुगतान वर्ष 2005 में ?67 करोड़ रूपये होता था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 415 करोड़ रूपये हो गया है। संग्राहकों के बच्चों के लिए एकलव्य शिक्षा योजना पिछले ग्यारह साल से चल रही है, जिससे अब तक 1712 बच्चों को शिक्षा के लिये 2 करोड़ एक लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

वन समितियों का माइक्रो प्लान

प्रदेश के एक तिहाई गाँव वन क्षेत्रों के अंदर या इसके आसपास बसे है। वहाँ के निवासियों की आजीविका वनों पर आधारित है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में इस साल के आखिर तक 5 हजार वन समितियो का माइक्रो प्लान तैयार करने का लक्ष्य है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ग्राम समुदाय अपनी आवश्यकता की वनोपज का उत्पादन कर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

ग्राम सभाओं को सौंपा अधिकार

वन समितियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का अधिकार अब ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। वन समिति की कार्यकारिणी में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लोगों को शामिल करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में अनेक प्रकार की वनोपज का उत्पादन होता है। इसमें महुआ, तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और विरौंजी प्रमुख है। पेसा कानून की भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों का पूरा अधिकार सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ऐसे निर्णय लिये गये हैं, जो वन समितियों से जुड़े संग्राहक परिवारों के लिये परिवर्तनकारी साबित हुए हैं। वन समितियों को भरपूर आर्थिक लाभ हुआ है। उदाहरण के लिये 32 वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से करीब 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। तेंदूपत्ता व्यापार के शुद्ध लाभ का 70 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत देने से 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है।

प्री-इवेंट कवरेज

Print Media

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

दक्षिण वन मण्डल सागर के अंतर्गत

आमेट के वीरान जंगल ने फिर हरियाली की चादर ओढ़ी

स्वदेश ज्योति संवाददाता, सागर

दक्षिण वन मण्डल सागर के अंतर्गत आमेट वन क्षेत्र की ग्राम वन समिति वीरपुरा ने बिगड़े वन क्षेत्र के सुधार का कार्य किया है।

समिति की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सदस्यों की मेहनत से आवंटित क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वनावारण बढ़ा और हरा.भरा हुआ है। वर्तमान में आवंटित क्षेत्र में वनों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके साथ ही समिति अपने क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों में रूचि लेकर कार्य कर रही है। संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विभाग की मेहनत ने बिगड़े वनों को सुधारा जा सका है। समिति अध्यक्ष श्रीमती इमरती बाई, उपाध्यक्ष सुमन दुबे रूचि लेकर सदस्यों के सहयोग से वीरान जंगल को हरा-भरा कर दिया। समिति द्वारा वन क्षेत्र के लोगों के उपयोग के लिये चौपाल चबूतरा बनवाया, पशुओं को पानी के लिये हौदी का निर्माण कराया। क्षेत्र में स्वास्थ शिविर लगवाकर लोगों का स्वास्थ परीक्षण कराया।

सराहनीय | **जिले के मझगवां बीट की वीरान पहाड़ी में जी उठा जंगल, ग्रामीणों ने पेश की संयुक्त वन प्रबंधन की अनूठी मिसाल**

जन सहभागिता से साढ़े छह सौ हेक्टेयर की पहाड़ी में हुआ बिगड़े वन का सुधार

ठूंठ और झाड़ियों के बाद कईप्रजाति के पेड़ लहलहाए। ● नईदुनिया

कटनी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। समाज की लापरवाही और मनुष्य द्वारा लगातार जंगल काटे जाने की वजह से कुछ साल पहले तक कटनी जिले के मझगवां की पहाड़ी गिने-चुने पेड़ों के तनों के ठूंठ और जंगली झाड़ियों तक सिमट गई थी, अब वहां मिश्रित प्रजाति के हजारों पेड़-पौधे लहलहा रहे हैं। अब यह पहाड़ी ग्रामीणों की जनसहभागिता और संयुक्त वन प्रबंधन से बिगड़े वनों के सुधार की मिसाल बन गई है। करीब 652 हेक्टेयर क्षेत्र के इस बिगड़े वन को वन समिति की सहभागिता और सक्रियता से नया जीवन मिला। पेड़-पौधों से उजड़ और वीरान हो चुकी मझगवां की इस पहाड़ी में अब जंगल जी उठा है। दरअसल कटनी शहर के नजदीक होने के कारण अत्यधिक जैविक दबाव, जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति एवं आस-पास के ग्रामीण इलाकों के करीब 4 हजार से अधिक पालतू पशुओं की चराई भी इसी वन क्षेत्र पर निर्भर थी। जिससे मझगवां का पूरा जंगल बिगड़े वन क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था।

मझगवां बीट के आरएफ-107, 108 से मझगवां, बंजारी, पौंडी, ढीमा, बिजौरी, उमड़ार गांव से लगा वन विभाग का 652 हेक्टेयर रिजर्व फारेस्ट है। मझगवां वन समिति के अध्यक्ष संतराम कुशवाहा ने बताया कि कुछ साल पहले जंगल नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गया था। वन विभाग ने इस क्षेत्र में वन सुधार के तहत काम करना शुरू किया और उसमें वन समिति के सदस्यों की मदद ली गई। 11 सदस्यीय वन ग्राम समिति ने वन विभाग के साथ पौधे रोपने के साथ ही उनके वृक्ष बनने तक और पुराने पेड़ों को सुरक्षित रखने की कवायद प्रारंभ की। उसका नतीजा यह है कि 652 हेक्टेयर वन भूमि वर्तमान में हरियाली से भरी है।

शहर से लगा यह वन क्षेत्र जहां आमजनों को आकर्षित करता है तो यहां जंगल में वन्य प्राणियों को भी सुरक्षित स्थान मिल रहा है। यहां पर वन विभाग ने वन्य प्राणियों को पानी पीने के लिए समाजसेवी संस्था के माध्यम से पौसरा की व्यवस्था की है और जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय सहित अन्य वन्य प्राणी निर्भय होकर विचरण करते हैं, जो यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र होते हैं।

वन मंडलाधिकारी कटनी आरसी विश्वकर्मा बताते हैं कि इस पहाड़ी को हरितिमा से आच्छादित करने में ग्रामीणों की समझ और सहभागिता प्रशंसनीय है। वन समिति के सदस्यों ने न केवल पेड़ों की देखरेख की बल्कि कटाई करने वालों को जंगल और पेड़ों का महत्व बताकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि सही मायनों में ग्रामीण ही इस पहाड़ी के पेड़-पौधों के सबसे बड़े रखवाले हैं। इनकी जिद और जुनून ने ही पहाड़ी को हरा-भरा कर दिया है। रेंजर एल.एन. चौधरी ने बताया कि अब इस पहाड़ी के घने जंगल में चीतल, सांभर, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर और सियार बड़ी संख्या में हैं साथ ही अनेक प्रजातियों के पक्षियों का भी कलरव सुनाई देता है।

वन समितियों के साथ चौकीदार भी करते हैं सुरक्षा : 652 हेक्टेयर के रिजर्व फारेस्ट के पेड़ों व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वर्तमान वन समिति अध्यक्ष संतराम कुशवाहा के साथ ही उपाध्यक्ष कली बाई, सदस्य चुन्नूबादी कोल, प्रीति कुशवाहा, कोमल प्रसाद चौधरी, लक्ष्मण प्रसाद सोनी, सुभाष कुशवाहा, संतोष कोल, सिकंदर कोल, बापी रसपकार भी रिजर्व फारेस्ट के पेड़ों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। बीट गार्ड शक्तिपाल सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वन क्षेत्र को सुधारने और पेड़ों, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए दो चौकीदार फूलचंद कोल व कुलीचंद कोल को भी तैनात किया गया है, जो वर्षों से ग्रामीणों, वन समितियों के सदस्यों के सहयोग से वन व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में 24 घंटे सेवाएं देते हैं। पहाड़ी के आसपास के ग्रामीणों को अब इस जंगल से गिरी-पड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी के अलावा तेंदूपत्ता, महुआ, अचार एवं अन्य वन औषधीय वनोपज उत्पाद भी प्राप्त हो रहे हैं।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6 दैनिक मध्यप्रदेश

कटनी, शुक्रवार 22 अप्रैल 2022

जिले के मझगंवा बीट की वीरान पहाड़ी में जी उठा जंगल

साढ़े छह : सौ हेक्टेयर की पहाड़ी में हुआ बिगड़े वन का सुधार, ग्रामीणों ने पेश की संयुक्त वन प्रबंधन की अनूठी मिसाल

कटनी दैमप्र। ग्रामीण जिले के एक वीरान हो चुके जंगल को हरा भरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक अनूठी मिसाल कायम की है कुछ साल पहले तक जिले के मझगंवा की पहाड़ी गिने-चुने पेड़ों के तनों के ठूंठ और जंगली झाड़ियों तक सिमट गई थी, आज वहां मिश्रित प्रजाति के हजारों पेड़-पौधे लहलहा रहे हैं। अब यह पहाड़ी ग्रामीणों की जनसहभागिता और संयुक्त वन प्रबंधन से बिगड़े वनों के सुधार की मिसाल बन गई है। करीब 652 हेक्टेयर क्षेत्र के इस बिगड़े वन को वन समिति की सहभागिता और सक्रियता से नया जीवन मिला। पेड़-पौधों से उजाड़ और वीरान हो चुकी मझगंवा की इस पहाड़ी में अब जंगल जी उठा है। दरअसल कटनी शहर के नजदीक होने के कारण अत्यधिक जैविक दबाव, जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति एवं आस-पास के ग्रामीण इलाकों के करीब 4 हजार से अधिक पालतू पशुओं की चराई भी इसी वन क्षेत्र पर निर्भर थी। जिससे मझगंवा का पूरा जंगल बिगड़े वन क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था।

हरियाली से भर उठा जंगल- मझगवां बीट के आरएफ-107,108 से मझगवां, बंजारी, पौड़ी, छैगरा, बिजौरी, उमाड़ार गांव से लगा वन विभाग का 652 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट है। मझगवां वन समिति के अध्यक्ष संतराम कुशवाहा ने बताया कि कुछ साल पहले जंगल नष्ट

होने की स्थिति में पहुंच गया था। वन विभाग ने इस क्षेत्र में वन सुधार के तहत काम करना शुरू किया और उसमें वन समिति के सदस्यों की मदद ली गई। 11 सदस्यीय वन ग्राम समिति ने वन विभाग के साथ पौधे रोपने के साथ ही उनके वृक्ष बनने तक और पुराने पेड़ों को सुरक्षित रखने की कवायद प्रारंभ की। उसका नतीजा यह है कि 652 हेक्टेयर वन भूमि वर्तमान में हरियाली से भरी है।

वन्य प्राणी निर्भय करते हैं विचरण- शहर से लगा यह वन क्षेत्र जहां आमजनों को आकर्षित करता है तो वहीं जंगल में वन्य प्राणियों को भी सुरक्षित स्थान मिल रहा है। यहां पर वन विभाग ने वन्य प्राणियों को पानी पीने के लिए समाजसेवी संस्था के माध्यम से पौसरा की व्यवस्था की है और जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय सहित अन्य वन्य प्राणी निर्भय होकर विचरण करते हैं, जो यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र होते हैं।

ग्रामीण बने पेड़-पौधों के सबसे बड़े रखवाले- वन मंडलाधिकारी कटनी आरसी विश्वकर्मा बताते हैं कि इस पहाड़ी को हरीतिमा से आच्छादित करने में ग्रामीणों की समझ और सहभागिता प्रशंसनीय है। वन समिति के सदस्यों ने न केवल पेड़ों की देखरेख की बल्कि कटाई करने वालों को जंगल और पेड़ों का महत्व बताकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि सही मायनों में ग्रामीण ही इस पहाड़ी के पेड़-पौधों के सबसे बड़े रखवाले हैं। इनकी जिद और जुनून ने ही पहाड़ी को हरा-भरा कर दिया है।

रेंजर एल.एन. चौधरी ने बताया कि अब इस पहाड़ी के घने जंगल में चीतल, सांभर, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर और सियार बड़ी संख्या में है साथ ही अनेक प्रजातियों के पक्षियों का भी कलरव सुनाई देता है।

वन समितियों के साथ चौकीदार भी करते हैं सुरक्षा

652 हेक्टेयर के रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ों व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वर्तमान वन समिति अध्यक्ष संतराम कुशवाहा के साथ ही उपाध्यक्ष कली बाई, सदस्य चुटुवादी कोल, प्रीति कुशवाहा, बोधन प्रसाद चौधरी, लक्ष्मण प्रसाद सोनी, सुभाष कुशवाहा, संतोष कोल, सिकंदर कोल, बाबी तरफदार भी रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। बीट गार्ड शक्तिपाल सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वन क्षेत्र को सुधारने और पेड़ों, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए दो चौकीदार फूलचंद कोल व दुलीचंद कोल को भी तैनात किया गया है, जो वर्षों से ग्रामीणों, वन समितियों के सदस्यों के सहयोग से वन व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में 24 घंटे सेवाएं देते हैं।

औषधीय वनोपज उत्पाद हो रहा प्राप्त

पहाड़ी के आसपास के ग्रामीणों को अब इस जंगल से गिरी-पड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी के अलावा तेंदूपत्ता, महुआ, अचार एवं अन्य वन औषधीय वनोपज उत्पाद भी प्राप्त हो रहे हैं। समिति द्वारा इन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या इससे अधिक दर पर विक्रय कर लाभांश के रूप में आय अर्जित हो रही है।

डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट

जिले के मझगवां बीट की वीरान पहाड़ी में जी उठा जंगल

जन सहभागिता से साढ़े छह: सौ हेक्टेयर की पहाड़ी में विभिन्न प्रजातियों के लगे पेड़-पौधे

कटनी (एक्सप्रेस)। समाज की लापरवाही और मनुष्य द्वारा लगातार जंगल काटे जाने की वजह से कुछ साल पहले तक कटनी जिले के मझगंवा की पहाड़ी गिने-चुने पेड़ों के तनों के ठूंठ और जंगली झाड़ियों तक सिमट गई थी, आज वहां मिश्रित प्रजाति के हजारों पेड़-पौधे लहलहा रहे हैं। अब यह पहाड़ी ग्रामीणों की जनसहभागिता और संयुक्त वन प्रबंधन से बिगड़े वनों के सुधार की मिसाल बन गई है। करीब 652 हेक्टेयर क्षेत्र के इस बिगड़े वन को वन समिति की सहभागिता और सक्रियता से नया जीवन मिला। पेड़-पौधों से उजाड़ और वीरान हो चुकी मझगंवा की इस पहाड़ी में अब जंगल जी उठा है। दरअसल कटनी शहर के नजदीक होने के कारण अत्यधिक जैविक दबाव, जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति एवं आस-पास के ग्रामीण इलाकों के करीब 4 हजार से अधिक पालतू पशुओं की चराई भी इसी वन क्षेत्र पर निर्भर थी। जिससे मझगंवा का पुरा जंगल बिगड़े वन क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। मझगवां बीट के आरएफ-107,108 से मझगवां, बंजारी, पौड़ी, छैगरा, बिजौरी, उमड़ार गांव से लगा वन विभाग का 652 हेक्टेयर रिजर्व फारेस्ट है। मझगवां वन समिति के अध्यक्ष संतराम कुशवाहा ने बताया कि कुछ साल पहले जंगल नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गया था। वन विभाग ने इस क्षेत्र में वन सुधार के तहत काम करना शुरू किया और उसमें वन समिति के सदस्यों की मदद ली गई। 11 सदस्यीय वन ग्राम समिति ने वन विभाग के साथ पौधे रोपने के साथ ही उनके वृक्ष बनने तक और पुराने पेड़ों को सुरक्षित रखने की कवायद प्रारंभ की। उसका नतीजा यह है कि 652 हेक्टेयर वन भूमि वर्तमान में हरियाली से भरी है। शहर से लगा यह वन क्षेत्र जहां आमजनों को आकर्षित करता है तो वहीं जंगल में वन्य प्राणियों को भी सुरक्षित स्थान मिल रहा है। यहां पर वन विभाग ने वन्य प्राणियों को पानी पीने के लिए समाजसेवी संस्था के माध्यम से पौसरा की व्यवस्था की है और जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय सहित अन्य वन्य प्राणी निर्भय होकर विचरण करते हैं, जो यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र होते हैं। वन मंडलाधिकारी कटनी आरसी विश्वकर्मा बताते हैं कि इस पहाड़ी को हरितिमा से आच्छादित करने में ग्रामीणों की समझ और सहभागिता प्रशंसनीय है। वन समिति के सदस्यों ने न केवल पेड़ों की देखरेख की बल्कि कटाई करने वालों को जंगल और पेड़ों का महत्व बताकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि सही मायनों में ग्रामीण ही इस पहाड़ी के पेड़-पौधों के सबसे बड़े रखवाले हैं। इनकी जिद और जुनून ने ही पहाड़ी को हरा-भरा कर दिया है। रेंजर एल.एन. चौधरी ने बताया कि अब इस पहाड़ी के घने जंगल में चीतल, सांभर, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर और सियार बड़ी संख्या में है साथ ही अनेक प्रजातियों के पक्षियों का भी कलरव सुनाई देता है।

वन समितियों के साथ चौकीदार भी करते है सुरक्षा

652 हेक्टेयर के रिजर्व फारेस्ट के पेड़ों व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वर्तमान वन समिति अध्यक्ष संतराम कुशवाहा के साथ ही उपाध्यक्ष कत्ती बाई, सदस्य चुटुवादी कोल, प्रीति कुशवाहा, बोधन प्रसाद चौधरी, लक्ष्मण प्रसाद सोनी, सुभाष कुशवाहा, संतोष कोल, सिकंदर कोल, बापी तरफदार भी रिजर्व फारेस्ट के पेड़ों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। बीट गार्ड शक्तिपाल सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वन क्षेत्र को सुधारने और पेड़ों, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए दो चौकीदार फूलचंद कोल व दुलीचंद कोल को भी तैनाम किया गया है, जो वर्षों से ग्रामीणों, वन समितियों के सदस्यों के सहयोग से वन व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में 24 घंटे सेवाएं देते हैं। पहाड़ी के आसपास के ग्रामीणों को अब इस जंगल से गिरी-पड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी के अलावा तेंदूपत्ता, महुआ, अचार एवं अन्य वन औषधीय वनोपज उत्पाद भी प्राप्त हो रहे हैं। समिति द्वारा इन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या इससे अधिक दर पर विक्रय कर लाभांश के रूप में आय अर्जित हो रही है।

खुशियों की दास्तान

ग्राम वन समिति ने ग्राम आवर में आवंटित क्षेत्र को घास बीड़ के रूप में किया विकसित

आगर मालवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में वन विभाग द्वारा जिले के ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है, जो कि वनों को विकसित कर उनका संरक्षण करने के साथ ही ग्राम विकास के कार्य भी करती है।

आगर मालवा जिला मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम आवर जहां वन विभाग द्वारा ग्राम वन समिति का गठन किया गया है। फॉरेस्ट विभाग द्वारा आवर ग्राम वन समिति को कक्ष-46 रकबा 100 हेक्टेयर संयुक्त वन प्रबंधन हेतु आवंटित किया गया है। ग्राम वन समिति के सचिव वनरक्षक पदम् परमार एवं सदस्य दिलीप सिंह परमार बताते है कि समिति द्वारा उक्त आवंटित क्षेत्र को घास बीड़ के रूप में विकसित किया गया है। विकसित बीड़ की देखरेख ग्राम वन समिति द्वारा की जाती है। आज इस क्षेत्र में पर्याप्त चारे की पैदावार होती है जो कि पशुओं का मुख्य आहार होता है। ग्राम वन समिति घास बीड़ के चारे को समीप स्थित गौशालाओं को प्रतिवर्ष नीलामी कर उपलब्ध करवाती हैसर्वाधिक चारा निर्धारित शुल्क में माधव गौशाला आगर में दिया जाता है। जिससे समिति को प्रतिवर्ष अच्छा लाभ प्राप्त होता है। वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक समिति को चारा नीलामी से कुल 5 लाख 95 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है। समिति द्वारा प्राप्त लाभ की राशि का उपयोग घास बीड़ की सुरक्षा और विभिन्न ग्राम विकास के कार्यों में किया जाता है।

ग्राम वन समिति शिवनी ने किया 26 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण

गढ़ी के जंगल में लगाए 32 हजार से अधिक पौधों में 80 प्रतिशत जीवित

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926033955

राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर जिले में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गठित ग्राम वन समिति शिवनी ने 26 हेक्टेयर में सघन पौधारोपण किया है, वहीं नाहर झाबुआ ने दो हजार हेक्टेयर जंगल को बचाए रखने का प्रयास किया है। अधिकृत जानकारी के मुताबिक, इंदौर जिले में कुल 116 ग्राम वन समितियां कार्यरत हैं। इनके माध्यम से वनों की सुरक्षा और वन क्षेत्र बढ़ाने में मदद भी मिल रही है। वन विभाग के एसडीओ एके श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम वन समिति शिवनी (गढ़ी) ने क्षेत्र में लगभग साढ़े 26 हेक्टेयर में 32 हजार 150 पौधे लगाए। लगातार देखभाल से पौधों को जीवित रखने में मदद मिली और 32 हजार 150 पौधों में से लगभग 26 हजार पौधे पूर्ण रूप से जीवित और सुरक्षित हैं। पौधों के जीवित रहने का प्रतिशत 80 से अधिक है। यह उपलब्धि बेहतर मानी जाती है। वन समिति के अध्यक्ष सलीम अकरम पटेल 40 सदस्यों के साथ पौधों की लगातार देखभाल कर रहे हैं। इसी तरह नाहर झाबुआ की वन समिति भी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। श्रीवास्तव के मुताबिक इस क्षेत्र में दो हजार के अधिक हेक्टेयर का वन क्षेत्र है।

प्री-इवेंट कवरेज

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

Print Media

वन ग्राम समिति की मेहनत से लौट रहा है वनों का खोया वैभव

सत्ता सुधार ■ भोपाल

वन विभाग ने माइक्रो प्लानिंग कर ग्राम वन समितियों के सहयोग से जंगलों की बहाली पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं। मंडला जिले का मनेरी वन ग्राम स्टाक मेपिंग (वर्ष 2004-14) क्षेत्र वनस्पति से रहित था और आरडीएफ (वन पुनर्घनत्वीकरण) के लिये चुना गया था। मनेरी ग्राम वन समिति का गठन कर उसे 186.92 हेक्टेयर वन प्रबंधन का काम सौंपा गया था। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास होने के कारण यह वन क्षेत्र गंभीर जैविक दबाव में था। बावजूद इसके स्थानीय समुदायों ने अवैध कटाई और चराई के खिलाफ वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2003-4 और

2005-6 के बीच यहाँ जंगल बहाली का काम शुरू हुआ। इस काम में ग्राम वन समिति मनेरी का नेतृत्व कर रही महिला सुश्री कल्लू बाई मार्को ने वन संरक्षण और प्रबंधन के लिये समुदाय को संगठित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। ग्राम वन समुदाय के अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प के चलते आज यह क्षेत्र वन से बहाल हो गया है। इतना ही नहीं, बीते 2 सालों में समुदाय ने 3 हजार 526 सागौन और 31 ईंधन के ढ़र की कटाई कर लाभ भी कमाया है।

जनजातीय ग्राम वन समिति ने बहाल किया 192 हेक्टेयर में जंगल

वन विभाग ने स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन और उनकी बहाली में शामिल करते हुए प्रदेश के खाली वन क्षेत्रों को वन सम्पदा से समृद्ध करने में कामयाबी हासिल की है। झाबुआ जिले की बड़ी नाल्दी ग्राम वन समिति को लगभग 15 साल पहले 192 हेक्टेयर खाली वन क्षेत्र को बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ग्राम वन समिति के सदस्य और ग्रामीणों द्वारा सालों से किये गये अथक प्रयासों से इस क्षेत्र का वन वैभव पुन- लौट आया है। जनजातीय समुदाय की आजीविका में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आकल्पन

जनसम्पर्क विभाग

मध्यप्रदेश शासन